HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 1-15 अगस्त, 2019

15 August 2019 हार्दिक शुभकामनाएं

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 1/ अंक 26/ पृष्ठ: 16 मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

स्वतंत्रता के मायने उत्तरदायित्व को आत्मसात करके ही समझे जा सकते हैं : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

स्वच्छ आईकोनिक क्षेत्रों में शामिल.....

यमनोत्री में यात्रियों के ट्रैकिंग रूट को स्वच्छ कर रहा आईआईआरडी

यात्रियों को सहूलियत के अलावा स्वच्छता का जिम्मा भी संभालेगी संस्था

द रीव टाइम्स : हेम राज चौहान

देश भर में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने में अपनी सेवाऐं दे रही संस्था आईआईआरडी अब यमनोत्री में भी यात्रियों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्रदान कर रही है। इस परियोजना में आईआईआरडी यमनोत्री में यात्रियों के लिए सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए गेल इंडिया के सौजन्य से कई प्रकार के कार्य कर रहा है। यात्रियों को सहूलियत के अलावा स्वच्छता का जिम्मा भी बखूबी संभाला है। इसके तहत यात्रियों को रास्ते में विश्राम करने के लिए सराय निर्माण, बैठने के लिए बैंच, यात्रा मार्ग में कूड़ेदानों को लगाना, खच्चरों के लिए समस्त उचित व्यवस्था करने से लेकर अन्य सुविधाओं को भी प्रदान की गई है। गेल इंडिया द्वारा प्रायोजित इस परियोजना में यमनोत्री में यात्रियों को भिन्न-भिन्न प्रकार की सेवाऐं प्रदान की की जा रही है। जानकी चट्टी से यमनोत्री मंदिर तक 5 कि.मी. मार्ग पर इन सुविधाओं में संस्था सेवाऐं प्रदान कर रही है । यमनोत्री के मौसम के हिसाब से वहां अत्यधिक ठंड होती है जिसके कारण यात्रियों के अलावा खच्चरों को भी दिक्कत होती है। इसके लिए आईआईआरडी गर्म पानी की समुचित व्यवस्था कर रहा है। आर. ओ. प्रणाली से स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है तथा पानी को गर्म रखने के लिए हीटर भी लगाए गए हैं जो कि टैंक आदि के साथ संबद्ध किए गए हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। खच्चरों के लिए भी पानी की खुरलियों का निर्माण रहा है जिसमें गर्म पानी की व्यवस्था रहती है । यात्रियों को आवश्यक जानकारी हेतु सहायता कक्षों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें यात्रा संबन्धि एवं अन्य जानकारियों को प्राप्त किया जा सकेगा। यमनोत्री में स्वच्छता को आधारभूत एवं प्राथमिकता सेवा मानते हुए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए शौचालयों का भी निर्माण किया जा रहा है। ये शौचालय यात्रियों की सुविधा तथा स्वच्छता को बनाए रखने के लिए खोले जा रहे हैं। इसके अलावा यात्रा मार्ग में बैच और कुर्सियों का प्रबन्ध किया है ताकि थकान के बाद यात्रि विश्राम कर सके। इसी प्रकार यमनोत्री में दो स्थान चिन्हित कर वहां यात्रियों के लिए चाय-पान का प्रबन्ध भी संस्था द्वारा किया गया है। यात्रि यहां जलपान करके मिशन रीव के अंतर्गत पौष्टिक स्पिरुलिना के उत्पादों का भी स्वाद ले सकते हैं। इन उत्पादों में स्पिरुलिना बिस्किट और कैपसूल आदि शामिल है। इसके अलावा मौसम के प्रतिकूल होने पर भी यात्रियों के लिए रेनकोट, छतरी आदि की व्यवस्था भी की गई है। यात्रियों को दिशा-निर्देश, आवश्यक जानकारी एवं मनोरंजन के लिए व्यवस्थित स्थलों पर एलईडी स्क्रीन को लगाया गया है। यमनोत्री को स्वच्छ रखने के लिए आईआईआरडी के स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की सेवाओं को लिया जा रहा है। यात्रियों द्वारा कूड़ा-कर्कट आदि जो भी यमुना अथवा इसके आस-पास फेंका गया है अथवा फेंका जाता है उसे उठाया जाता है तथा समुचित स्थान पर उसका निदान किया जा रहा है। यात्रियों को प्लास्टिक या अन्य व्यर्थ वस्तुओं को यत्र-तत्र या नदी में न फेंकने के लिए साइन बोर्ड आदि लगा कर जागरुक किया जा रहा है। यात्रियों को अन्य माध्यमों से भी जानकारी दी जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से आईआईआरडी यमनोत्री धाम को यात्रियों के लिए अति सुगम्य, स्वच्छ एवं यात्रा को आनंद में परिवर्तित करने के प्रति संकल्पबद्ध है। गेल इंडिया के इस प्रयास को संस्था शतप्रतिशत सफल रुप में तीर्थयात्रियों के लिए पूरी करने के लिए प्रयासरत है ।

यमनोत्री में आईआईआरडी ने स्वच्छता पखवाड़ा में की शिरकत

यमनोत्री में आईआईआरडी द्वारा गेल इंडिया की वृहद् योजना पर सेवाओं के साथ-साथ स्वच्छता अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है । इसी के तहत यमनोत्री में गेल इंडिया द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली बच्चों के अलावा गेल इंडिया के पदाधिकारियों के साथ आईआईआरडी की ओर से भी प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा की अगुवाई में शिमला से टीम ने भाग लिया तथा यमुना की सफाई की। गेल इंडिया से जनरल मैनेजर अनूप गुप्ता, कार्यकारी निदेशक प्रसून कुमार, वरिष्ठ अधिकार दीपक कुमार एवं सानु कुमार रजक ने इसमें शिरकत की। इसके अलावा यमुना के आस-पास भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा के साथ, निदेशक सुषमा शर्मा, फूलायर ग्रुप के निदेशक व सीईओ आन्नद नायर, आईएफटीआई के सीओओ रंजन मोहंती, आईआईआरडी के कंपनी सचिव अभिमन्यु कवंर और परियोजना अधिकारी आईआईआरडी विशाल शर्मा भी शामिल हुए। इस अवसर पर स्वच्छता अभियान के अलावा लोगों को जागरुक भी किया गया।

राजनीति और समाजसेवा की मिसाल सुषमा स्वराज की भावभीनी विदाई

द रीव टाइम्सः पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की सर्वमान्य नेत्री सुषमा स्वराज ने 6 अगस्त को आख़िरी सांस ली और अपने पीछे छोड़ गई एक बहुत बड़ी राजनैतिक और सामाजिक विरासत जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा रहेगी। सुषमा स्वराज सबसे कम उम्र में अंबाला से विधायक बन कर कम उम्र में ही हरियाणा में देवीलाल सरकार में मंत्री भी रही। भाजपा के सर्वोच्च पदों को भी सुशोभित करते हुए उन्होंने एक लंबा संघर्षपूर्ण समय लोगों की सेवा में लगाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर मोदी सरकार में इससे पूर्व वो विदेश मंत्री भी रहीं और उन्हें विदेशों में भारतीयों के अधिकारों के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए सदा याद किया जाता रहेगा । उनकी क्षति सबके लिए अपूर्णणीय है। सुषमा स्वराज ने अपने आख़िरी उद्गार में दुनिया को अलविदा कहने से पूर्व ट्विट किया कि 370 पर सरकार के निर्णय को अपनी जीवन भर की प्रतीक्षा का सफल अंजाम बताया। देश और विदेशों में भी उनके देहांत पर शोक की लहर है।

जम्मु कश्मीर को मिली अब नई आज़ादी

370 हटी, राज्य का दर्ज़ा छीना, बना केन्द्र शासित राज्य

लद्दाख भी अब केन्द्र के अधीन, देश भर में जश्न का माहौल

द रीव टाइम्सः हेम राज चौहान

आतंकवाद और असमानता के दंश से जूझ रहे जम्मु-कश्मीर को ५ अगस्त को मुक्ति मिल ही गई। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति की अनुशंसा पर कश्मीर से ३७० को हटाकर स्वतंत्र राज्य का दर्ज़ा भी छीन लिया तथा जम्मु व कश्मीर को केन्द्र शासित राज्य बना दिया। लद्दाख को भी केन्द्र के अधीन कर पिछले दिनों से चल रही अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया। राज्यसभा में प्रस्ताव के आने से पूर्व केबिनेट की अहम बैठक हुई और फिर नागपंचमी के दिन गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में प्रस्ताव रखते हुए जानकारी दी। खूब हो-हंगामे के बीच जैसे ही कश्मीर पर जानकारी दी गई, पूरा देश खुशी से झूम उठा। सभी राज्यों में लोगों ने सड़कों पर उतर कर जश्न मनाया तथा इसे कश्मीर की वास्तविक आज़ादी का नाम देकर सरकार के इस क़दम की मुक्तकंठ से प्रशंसा की ।

कश्मीर में कर्फ़्यु लगाकर महबूबा मुफ़्ती और उमर अबदुल्ला को हिरासत में ले लिया गया तथा कानून और व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी सेना ने अपने हाथों में ले ली। कश्मीरी पंडितों ने भी इसे ऐतिहासिक क़दम बताते हुए न्याय की उम्मीद की। उधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमित शाह की पीठ थपथपाकर बधाई दी ।

कांग्रेस पार्टी ने इसे कश्मीर और कश्मीरियत का मर्डर करार देते हुए विरोध किया। अधिकतर राजनैतिक दल मोदी सरकार के इस फैसले से सहमत दिखे तथा समर्थन में उतर आए ।

अब क्या होगा

- कश्मीर में अब कोई भी ज़मीन ख़रीद सकता है ।
- अंतर्राज्जीय विवाह हो सकते हैं साथ ही वहां की लड़कियों की नागरिकता बनी रहेगी ।
- दोहरी नागरिकता भी ख़त्म हो गई है ।
- एक देश एक संविधान लागु होगा ।
- पर्यटन की संभावनाओं के मध्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा ।

परियोजना के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा

IIRD has always believed in sustainable development where humans may benefit and the nature, environment can be protected. Hence, time and again we have propagated the activities that may support the Swachh Bharat Abhiyan.

Providing support to Yamunotri Pilgrims in Uttarakhand under the Swachh Iconic Places via the collaborative effort by IIRD and GAIL India to ensure facilitation of the pilgrims and boost sanitation, cleanliness of the revered environment along the trekking route to Yamunotri.

6 Toilets for better sanitation along the revered trekking route

15 Dustbins installed for cleanliness

2 Bottle Crushers for proper waste management

10 Benches installed for the facilitation of the pilgrims

2 RO water purifiers along with **2** Hot Water stations for the mules

8 Electrical Water Heaters have also been set up **Pilgrims Facilitation Centre** has also been set up which includes

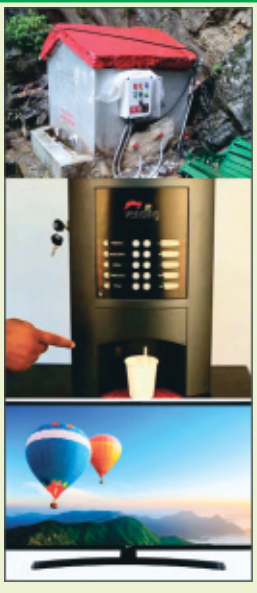

2 Coffee Vending Machines

2 Televisions for the facilitation of the pilgrims

15 Environment Assistants have been appointed to oversee the smooth implementation and success of this programme who have been recruited from the local regions and have been provided with a livelihood skill and a source of earning

प्रदेश के पूर्व और गुजरात के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के साथ-साथ अन्य सम्माननीयों एवं बुद्धिजीवियों के 'द रीव टाइम्स' की वर्षगांठ पर बधाई संदेश

Acharya Devvrat
Governor
Himachal Pradesh

सत्यमेव जयते

आचार्य देवव्रत
राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

सन्देश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि शिमला से प्रकाशित होने वाले पाक्षिक समाचार पत्र **"द रीव टाइम्स"** प्रकाशन का एक वर्ष पूरा कर चुका है ।

सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासशील योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुँचाने में समाचार पत्रों का विशेष योगदान रहता है । हिमाचल प्रदेश बागवानी के लिए पूरे देश में जाना जाता है । इस वर्ष केन्द्रीय सरकार के बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए समुचित बजट का प्रावधान किया गया है । इसके अलावा हिमाचल में भी सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध करवाया गया है ।

हिमाचल के आर्थिक विकास में प्राकृतिक खेती आने वाले वर्षों में अहम भूमिका निभाने वाली है ।

मुझे विश्वास है कि आपके समाचार पत्र के माध्यम से इस विषय का अधिक से अधिक प्रसार प्रचार किया जाएगा, जिससे प्रकृति और पर्यावरण दोनों का संरक्षण हो, क्योंकि समाचार पत्र समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं ।

मैं समाचार पत्र की वर्षगांठ के अवसर पर अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ ।

(आचार्य देवव्रत)

जय राम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश सरकार

मुख्य मन्त्री
हिमाचल प्रदेश
शिमला-171 002

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि पाक्षिक समाचार पत्र 'द रीव टाइम्स' ने अपने प्रकाशन का एक वर्ष पूरा कर लिया है और अब दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है।

यह प्रशंसनीय है कि 'द रीव टाइम्स' ने अपने इस सफर में हिमाचल के विकास, साहित्य, सांस्कृतिक विरासत जैसे क्षेत्रों को प्रमुखता से उठाया है। समाचार पत्र-पत्रिकाएं, न्यूज एजेंसियां एवं न्यूज चैनल समाचार सम्प्रेषण के साथ-साथ जनचेतना एवं समाज को दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

मुझे विश्वास है कि 'द रीव टाइम्स' पाक्षिक समाचार पत्र सरकार द्वारा आम लोगों के हित में लिए गए निर्णयों, कार्यक्रमों एवं नीतियों को उचित स्थान देकर अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन करेगा।

समाचार पत्र के 25वें अंक के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(जय राम ठाकुर)

दूरभाष : (का०) +91-177-2625400, (आ०) +91-177-2621384, 2627529, फैक्स : +91-177-2625011 ईमेल : cm-hp@nic.in

हिमाचल प्रदेश सरकार

मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश,
शिमला-171002.

No. 2904 dt. 08-07-2019

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स के प्रकाशन का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। इस अवसर पर समाचार पत्र द्वारा जुलाई माह में 25वां अंक प्रकाशित किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार ने सदैव मीडिया के माध्यम से जनता के बीच सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की है। मीडिया सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके द्वारा समाज के विकास को गति मिलती है। द रीव टाइम्स ने अपने समाचार पत्र मे जन समुदाय की समस्याओं, आवश्यकताओं तथा कल्याणकारी योजनाओं को सजगता, निष्पक्षता एवं कर्मठता से उठाया है।

मुझे आशा है कि समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए द रीव टाइम्स सदैव सत्याधारित पत्रकारिता जारी रखेगा।

मेरी ओर से समाचार पत्र की वर्षगांठ तथा 25वें अंक के प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

(सुरेश भारद्वाज)

वीरेन्द्र कंवर

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास, पंचायती राज,
पशुपालन एवं मत्स्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि 'द रीव टाइम्स' के प्रकाशन का एक सफल वर्ष पूरा हो गया है। इस पाक्षिक समाचार पत्र के पहले अंक का प्रकाशन 01 जुलाई, 2018 को हुआ था तथा इस छोटी अवधि में इसने पाठकों में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है।

'द रीव टाइम्स' ने लोगों की प्रत्येक बात को सरकार तक एवं सरकार की प्रत्येक जानकारी, नीतियों तथा कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके निष्पक्ष प्रयासों से समाज को निरंतर कल्याणकारी जानकारी हासिल हो रही है।

मैं 'द रीव टाइम्स' के समस्त समूह को उनकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

(वीरेन्द्र कंवर)

कार्यालय : कमरा नं. 221, द्वितीय मंजिल, इलर्जली बिल्डिंग, हि.प्र. सचिवालय, शिमला-171002

प्रदेश के सम्माननीयों एवं बुद्धिजीवियों के 'द रीव टाइम्स' की वर्षगांठ पर बधाई संदेश

बी. के. अग्रवाल, भा.प्र.से.
मुख्य सचिव
B. K. AGARWAL, IAS
Chief Secretary

हिमाचल प्रदेश सरकार

एलर्सली,
हिमाचल प्रदेश सचिवालय-171 002
दूरभाष : 0177-2621022
ई-मेल : cs-hp@nic.in
Ellerslie,
HP Secretariat-171 002
Tele. : 0177-2621022
E-mail : cs-hp@nic.in

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि पाक्षिक समाचार पत्र 'द रीव टाइम्स' ने अपने प्रकाशन का पहला सफल वर्ष पूर्ण कर लिया है । 1 जुलाई 2018 को आरम्भ हुए इस समाचार पत्र ने इस छोटी अवधि में सफलता के नये आयाम तय कर पाठकों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है ।

'द रीव टाइम्स' प्रदेश में जन कल्याण की योजनाओं के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ जन अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुझे विश्वास है कि 'द रीव टाइम्स' समाजिक गतिविधियों में इसी प्रकार अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा।

मैं 'द रीव टाइम्स' के सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

(बी0के0अग्रवाल)

Kusum Sadrate
Mayor
Municipal Corporation Shimla

Office : 0177-2812360
Mobile : 94597-95447
E-mail : mcs_shimla@yahoo.com
mayor.mcs@hp.gov.in
Valancia Estate, Lower Kaithu
Annadale, Shimla-171003

Ref. No. :
Date :

संदेश

द रीव टाइम्स समाचार पत्र के एक वर्ष पूरा करने पर मैं इस समाचार पत्र समूह को हार्दिक बधाई देती हूँ । द रीव टाइम्स समाचार पत्र ने मात्र एक वर्ष में निष्पक्ष पत्रकारिता और सत्याधारित खबरों को ही स्थान दिया। इस समाचार पत्र ने खबरों को जांच–परख की कसौटी पर तोल कर पाठकों के सामने रखा।

नगर निगम शिमला की विकासात्मक खबरों को भी समय–समय पर समुचित स्थान मिलता रहा है। विगत एक वर्ष में नगर निगम ने जो अभूतपूर्व विकास कार्य किए न केवल उनको लोगों एवं सरकार तक पहुँचाने में द रीव टाइम्ज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

द रीव टाइम्स में सम–सामायिक विषयों पर संपादकीय एवं अन्य लेखों के माध्यम से पाठकों को विश्लेषणात्मक जानकारी की उपलब्धता बनी हुई है, जिसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर समाचार पत्र को बधाई देती हूँ। केन्द्रिय एवं राज्य सरकार की योजनाओं को विशेष पृष्ठों पर श्रृंखलाबद्व स्थान देना अपने आप में समाचार पत्र की सामाजिक जिम्मेवारी को दर्शाता है। 15 दिनों की समस्त महत्वपूर्ण खबरों को भी उचित स्थान मिला है। मिशन रीव और आईआईआरडी के सामाजिक प्रयासों की भी खबरों ने जानकारी में इज़ाफा किया है।

मैं पुनः द रीव टाइम्स की वर्षगांठ के अवसर पर सभी को बधाई देती हूँ तथा विशेषकर प्रधान संपादक डा0 एल.सी.शर्मा एवं संपादकीय टीम को सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक शुभकानाएं देती हूँ।

कुसुम सदरेट
महापौर,
नगर निगम शिमला।

डा. आर. एन. बत्ता
सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

हिमाचल प्रदेश सरकार

एलर्जली,
शिमला–171 002

दिनांक: शिमला–2, 9 जुलाई, 2019

सन्देश

यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि 'द रीव टाइम्स' ने सफलतापूर्वक अपना एक वर्ष पूरा कर लिया है। इस पत्रिका का पहला अंक 1 जुलाई, 2018 में प्रकाशित किया गया था।

'द रीव टाइम्स' द्वारा जन समुदाय की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं व सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समय–समय पर प्रकाशन किया जाता रहा है। इनके निरंतर प्रयासों से समाज को सजगता के अलावा निर्लेप एवं निष्पक्ष जानकारी हासिल हो रही है।

मैं 'द रीव टाइम्स' के समस्त समूह को उनकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

(आर.एन. बत्ता)

Commissioner
Municipal Corporation Shimla
Phone : 0177-2812899
Fax : 0177-2802346

D.O. No. : MCS/Com/19-31
Date...16-7-19..........

संदेश

द रीव टाइम्स समाचार पत्र के एक वर्ष पूरा करने पर मैं इस समाचार पत्र समूह को हार्दिक बधाई देता हूँ । द रीव टाइम्स समाचार पत्र ने मात्र एक वर्ष में निष्पक्ष पत्रकारिता और सत्याधारित खबरों को ही स्थान दिया। इस समाचार पत्र ने खबरों को जांच–परख की कसौटी पर तोल कर पाठकों के सामने रखा।

नगर निगम शिमला की विकासात्मक खबरों को भी समय–समय पर समुचित स्थान मिलता रहा है। विगत एक वर्ष में नगर निगम ने जो अभूतपूर्व विकास कार्य किए न केवल उनको लोगों एवं सरकार तक पहुँचाने में द रीव टाइम्ज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

द रीव टाइम्स में सम–सामायिक विषयों पर संपादकीय एवं अन्य लेखों के माध्यम से पाठकों को विश्लेषणात्मक जानकारी की उपलब्धता बनी हुई है, जिसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर समाचार पत्र को बधाई देता हूँ। केन्द्रिय एवं राज्य सरकार की योजनाओं को विशेष पृष्ठों पर श्रृंखलाबद्व स्थान देना अपने आप में समाचार पत्र की सामाजिक जिम्मेवारी को दर्शाता है। 15 दिनों की समस्त महत्वपूर्ण खबरों को भी उचित स्थान मिला है। मिशन रीव और आईआईआरडी के सामाजिक प्रयासों की भी खबरों ने जानकारी में इज़ाफा किया है।

मैं पुनः द रीव टाइम्स की वर्षगांठ के अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ तथा विशेषकर प्रधान संपादक डा0 एल.सी.शर्मा एवं संपादकीय टीम को सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक शुभकानाएं देता हूँ।

पंकज राय
आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

सफलता भरा एक वर्ष.... कृषि

करीब दो साल पूर्व मिशन रीव की शुरूआत आज हिमाचल के गांवों की तस्वीर को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुई। बात कृषि की हो, दूर दराज के गांवों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने की हो, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की हो या बात हो तकनीकी और वित्तीय सुविधा की, मिशन रीव इन सब में इक्कीस ही साबित हुआ। बिते वर्ष 15 जुलाई 2018 को मिशन रीव की विभिन्न उपलब्धियों की फेहरिस्त में एक नया अध्याय जुड़ गया। ये अध्याय था पाक्षिक समाचार पत्र के तौर पर **'द रीव टाइम्स'** की शुरूआत। शुरूआत से अब तक इस समाचार पत्र के माध्यम से जहां मिशन रीव की विभिन्न सेवाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाया वहीं सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी आम लोगों तक पहुंचाया। साथ ही देश-दुनिया घटनाओं से हिमाचल के गांवों को अवगत कराने और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में भी **'द रीव टाइम्स'** ने महत्पूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं खास कर कृषि से जुड़ी जानकारी देने में भी अहम योगदान दिया। **'द रीव टाइम्स'** के इस अंक में हम मिशन रीव की उपलब्धियों के साथ समाचार पत्र के एक वर्ष के सफर से भी आपको रूबरू करा रहे हैं।

हिमाचल को जैविक राज्य बनाने में दिया अहम योगदान..

हिमाचल की मिट्टी को रासायनिक खादों के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए मिशन रीव के तहत हिमाचल के किसानों को जैविक खाद का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। किसानों को जैविक खाद बनाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैविक खाद के बारे में गांव के लोगों को जानकारी देने में द रीव टाइम्स ने भी अहम भूमिका निभाई। बीते एक वर्ष के दौरान प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में ग्रामीणों को प्रशिक्षण देकर मिशन रीव के तहत जैविक खाद का भंडार तैयार किया गया है। सोलन, शिमला, चंबा और ऊना में मिशन रीव के तहत गांव के लोगों को जैविक खाद का प्रशिक्षण दिया गया। इतना ही नहीं ग्रामीणों द्वारा तैयार खाद के लिए मिशन रीव के तहत ही बाजार भी उपलब्ध करवाया गया। ग्रामीणों को उनके घर पर ही खाद के अच्छे दाम मिशन रीव के तहत दिलवाए गए। प्रशिक्षण के बाद किसानों ने खाद बनाना शुरू की और इसमे सफल रहे। जिला चंबा से संबंध रखने वाले रामसिंह का कहना है कि कुछ माह पहले ही उन्होंने मिशन रीव के तहत जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने जैविक खाद बनानी शुरू की। इस कार्य को करने में मिशन रीव के प्रतिनिधियों की ओर से पूरा सहयोग किया गया। इसके बाद इस खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करने के साथ ही दूसरे लोगों को भी खाद उपयोग करने के लिए दी। इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आए। रामसिह की तरह ही जिला चंबा में आज दूसरे किसान भी जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने खेतों को रासायनिक खादों के दुष्प्रभावों से बचाकर बेहतर और गुणवत्ता पूर्वक फसलें पैदा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस खाद को तैयार करने के लिए जीरो बजटिंग खेती के तहत आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की ओर से गांव-गांव जाकर किसानों और बागवानों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की निगरानी में गांव वालों से खाद तैयार करवाई गई और उनसे खरीदकर मिशन रीव के तहत उन्हें खाद की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराया गया है।

सोलन से किन्नौर और चंबा पहुंचाई जैविक खाद

किन्नौर के कई क्षेत्रों भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहां तक कोई सामान पहुंचाना किसी चुनौति से कम नहीं है। लेकिन मिशन रीव ने इस चुनौति को स्वीकार किया और यहां के बागवानों को जैविक खाद मुहैया करवाई। किन्नौर के बागवान अपने बागीचों में जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मिशन रीव से खाद किन्नौर पहुंचाने का आग्रह किया। इसके बाद मिशन प्रतिनिधियों ने जिला सोलन से किन्नौर के बागवानों को खाद उनके घर तक पहुंचाई। इसी तरह जिला चंबा के दूर दराज के गांवों में भी मिशन रीव के तहत खाद की आपूर्ति बागवानों और किसानों को उनके घर तक उपलब्ध करवाई गई। चंबा, किन्नौर और सोलन की तरह की प्रदेश के दूसरे जिलों में भी मिशन रीव के तहत ग्रामीणों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए विशेष निःशुल्क शिविरों का आयोजन किया गया और उनकी आर्थिकी को मजबूत करने में सहयोग दिया गया।

जब गांव तक पहुंचाए उन्नत कृषि उपकरण और बीज...

सरकार ने किसानों के लिए सोलर स्प्रे पंप देने की योजना तो शुरू कर दी। लेकिन किसानों तक वह कैसे पहुंचे इसके लिए कोई स्टीक व्यवस्था नहीं हो पाई। ऐसे में आईआईआरडी का मिशन रीव किसानों के लिए मार्गदर्शक के तौर पर उभरा। मिशन के सदस्यों ने जहां किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी वहीं इन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने में भरपूर मदद की। जिला सोलन, मंडी और चंबा में इसके कई जीवंत उदाहरण हैं। इनमें से एक है सोलर स्प्रे पंप। जिला में किसानों को मिशन रीव के तहत सोलर पंप उपलब्ध कराए गए और साथ ही मटर समेत अन्य फसलों के बीज भी किसानों को उनके घर तक पहुंचाने में रीव ने मदद की। इसी तरह मंडी के मेद राम कहना है कि पहले जैसे ही स्प्रे करने का सीजन आता था वैसे ही हम सोच में पड़ जाते थे कि साधारण पंप से सही स्प्रे कैसे करें। फिर सरकारी पंप के बारे में सुना लेकिन पंप कैसे और कहां से मिलेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद मिशन रीव के प्रतिनिधियों ने योजना की पूरी जानकारी दी। इतना ही नहीं पंप घर तक पहुंचा दिया गया। मेदराम की तरह ही प्रदेश के विभिन्न पंचायतों में कई किसान और बागवान है जो रीव सोलर स्प्रे पंप से अपनी फसलों और बागीजों की देखभाल कर रहे हैं।

मृदा जांच भी हुई आसान

हिमाचल के गांवों में किसानों को आधुनिक तरीके से कृषि करने में भी मिशन रीव ने एक सहयोगी के तौर पर तत्परता से काम किया। जैविक खाद के साथ ही रीव के तहत गांवों में मृदा जांच की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। इस सुविधा का लाभ शिमला, सोलन समेत प्रदेश के दूसरे जिलों के किसानों बागवानों ने खूब उठाया। किसानों और बागवानों से मृदा सैंपल एकत्र करने के लिए गांव में ही मिशन रीव के तहत विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। इसके बाद इन सैंपल का शिमला स्थित मृदा परीक्षण लैब में परीक्षण किया गया और किसानों बागवानों को उनके घर पर ही रिपोर्ट भी उपलब्ध की गई। अब मिशन रीव के तहत सभी जिलों में मृदा परीक्षण लैब स्थापित करने की भी योजना है।

मृदा जांच : खेत की मिट्टी के गुणों के हिसाब से उगाई जाएंगी फसलें

द रीव टाइम्स ब्यूरो: (हेम राज चौहान)

हिमाचल में अभी भी किसानों के पास अपने खेतों की मिट्टी के परीक्षण की कोई सुगम तकनीक न होने के कारण सभी खेतों की मिट्टी को जांच के दायरे में लाना मुश्किल सा कार्य है। इसके लिए आईआईआरडी ने बहुत ही उपयोगी तकनीक और सुगम प्रक्रिया से किसानों को राहत दी है। गांव-गांव में किसानों के खेतों से मिट्टी परीक्षण के लिए नमूने लिए जाते हैं तथा गांव में ही मृदा जांच मशीन की उपलब्धता के कारण उनके नमूनों की जांच कर उन्हें रिपोर्ट दी जाती है। अमूमन, मृदा जांच के लिए उपयोग होने वाली मशीन की लागत मंहगी होती है। साथ ही इसे एक ही स्थान पर स्थापित कर मृदा जांच की जाती है। इससे दूरदराज के किसान इससे अछूते रहते हैं और समय-समय पर अपने खेतों की मिट्टी को जांच हेतु नहीं ले जा सकते हैं। आईआईआरडी ने किसानों की इस समस्या को अति सरल करते हुए सुगम मृदा जांच मशीन को प्रदेश के किसानों के लिए गांव में ही उपलब्ध करवाने को सराहनीय कार्य किया है। अब किसानों को मिट्टी की जांच हेतु न तो दूर जाने की आवश्यकता है और न ही यह बहुत मंहगा है। यह एक पोर्टेबल मशीन है। इसे गांव में ले जाकर वहीं खेतों से मिट्टी के नमूने लेकर जांच की जाती है और किसानों को रिपोर्ट के आधार पर रीव जैविक खाद दी जाती है।

मंहगी मशीन की औपचारिकताओं से मुक्त होगें गांव-गांव सुगम रीव मृदा जांच मशीन से लाभान्वित होगे किसान

कैसे काम करती है यह सुगम मृदा जांच मशीन

यह एक छोटी मशीन है जिसे सुगमता से कहीं भी ले जाकर स्थापित किया जा सकता है। मुख्यतः यह 12 प्रकार के मृदा परीक्षण करती है जिनमें कुछ ये हैं :

- वृहद्/मैक्रो पौष्टिक तत्वों की जांच : नाईट्रोजन,फासफोरस एवं पोटाशियम
- सूक्ष्म/माइक्रो पौष्टिक तत्वों की जांचः आयरन, कॉपर, जिंक, मैगजीन आदि
- पी एच जांच प्रकिया
- ई सी जांच : इसमें मिट्टी में नमक की मात्रा की जांच होती है। मिट्टी में जितना कम नमक होगा, उसकी गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। इसी के आधार पर बैक्टिरिया तैयार कर रीव खाद बनाई जाती है ताकि वांछित मृदा गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके।
- ऑक्सीजन स्तर की जांच

मृदा जांच क्यों ज़रुरी

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि लगातार कीटनाशकों के अतिउपयोग के कारण ज़मीन ने अपने पौष्टिक तत्वों को निचले स्तर पर ला दिया है। ऐसे में किसान पारंपरिक तौर-तरीकों से मिट्टी की जांच करते थे, क्योंकि वैज्ञानिक तकनीक न के बराबर ही थी। लेकिन अब ज़मीन की जांच को वैज्ञानिक तरीके से ही जांचने की प्राथमिक आवश्यकता है। मंहगा और दुर्गम जांच प्रक्रिया होने के कारण आज भी किसान नियमित जांच नहीं करवाते हैं। यदि जांच करवाने की विवशता आ ही जाती है तो केवल एक या दो खेतों से ही मिट्टी जांच करवाते हैं। जबकि सभी खेतों की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता भिन्न होती है। जांच के लिए हर खेत से मिट्टी के नमूने के आधार पर ही उस खेत में मौजूद पौष्टिक तत्वों के आधार पर ही फसलों को उगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है।

(मृदा जांच क्यों, कैसे और कहां हो...)

किसान और सेवाओं के बीच मिशन रीव बनेगा सेतु

मिशन रीव के पंचायत फेसिलिटेटर गांव में किसानों के खेतों से मिट्टी के नमूने जांच हेतु लेगें तथा जांच उपरांत आवश्यक पोषक तत्वों से तैयार रीव ऑर्गेनिक खाद को किसानों को घर पर ही उपलब्ध करवाऐगें। गांव के किसान इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि मिट्टी के पोषक तत्वों के आधार पर की गई खेती कितनी लाभप्रद होती है। और यह भी दीगर है कि प्रत्येक खेत की मिट्टी के गुण भिन्न होते हैं जिसके आधार पर खेती को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए अलग-अलग खेतों की मिट्टी की जांच करना आवश्यक है। इसी को आधार मानकर मिशन रीव के तहत इस लघु मृदा जांच मशीन से गांव में पृथक जांच की जाएगी ताकि खेतों के पौष्टिक तत्वों के आधार पर रीव जैविक खाद का निर्माण किया जा सके। जब खाद मृदा जांच के आधार पर तैयार की जाएगी तो फसलें भी खेतों में उसी हिसाब से उगाई जा सकेगी।

क्या कहते हैं किसान ?

हिमाचल प्रदेश में मृदा जांच के लिए महीनों प्रतीक्षा करने के बाद यदि एक खेत की मिट्टी जांच हो भी जाती है तो उसके परिणाम आने में भी महीनों लग जाते थे। इसका कोई भी लाभ समय रहते किसान नहीं उठा पाते थे। किंतु मिशन रीव के तहत मृदा जांच प्रतिदिन होगा और उसी समय उसका परिणाम यानि रिपोर्ट भी दे दी जाएगी। कृषक नंद लाल कहते हैं कि उन्होंने पंचायत में अक्सर मृदा जांच के लिए आवेदन किया। एक-दो बार सैंपल लिए भी गए जिसका परिणाम बहुत देरी से प्राप्त हुआ। इतनी देरी से परिणाम आने का क्या लाभ जबकि तब तक दूसरी फसल लगाने का समय आ जाता है। मिशन रीव के लोग मेरे घर पर आकर मृदा जांच हेतु सैंपल हर खेत से एकत्रित कर उसकी रिपोर्ट देने की बात कर गए हैं जो कि मेरे लिए बेहद खुशी की बात रही।

जांच के बाद क्या

आगे क्या ?

सोलर पंप योजना को लोगों तक पहुंचाएगा मिशन रीव
जानकारी से लेकर पंप लगाने तक में सहयोग करेंगे मिशन रीव प्रतिनिधि

टीम रीव, कुल्लू

अगर आप सरकार की किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसकी जानकारी के लिए आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसी भी सरकारी योजना की जानकारी अब आपको मिशन रीव प्रतिनिधि आपके घर पर ही उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने में भी मिशन रीव प्रतिनिधि पूरा सहयोग करेंगे। इसी अभियान के तहत किसान उर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान (कुसुम) योजना का लाभ गांव के किसानों तक पहुंचाने में भी मिशन रीव सहयोग कर रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह जिला कुल्लू में भी किसानों को इस योजना का लाभ लेने में सहयोग किया जाएगा।

क्या है सौर पंप योजना

साल 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप सेट खरीदने पर 90 से 100 फीसदी तक सब्सिडी देने का फैसला किया है।

कृषि और बागवानी उपज बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस साल के बजट में 20 करोड़ रुपये से सौर पंप योजना की शुरुआत की है। सौर पंप योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2018 से की गयी है।

इसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप खरीदने पर 90-100 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। योजना के मुताबिक अगर किसान अकेले पंप लगवाना चाहता है तो पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से 90 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है जबकि समूह बनाकर पंप लगवाने और पानी के स्त्रोत का प्रावधान होने पर 100 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है।

दरअसल किसान अब तक डीजल या बिजली से चलने वाले पंप से फसलों की सिंचाई करते हैं। इससे कृषि की लागत बढ़ती है। बिजली से चलने वाले सिंचाई प्रोजेक्ट पर भी लागत अधिक आती है। अब सौर पंप योजना से प्रदेश के करी दस लाख किसानों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत सौर पंपों से सिंचाई के लिए पानी को उठाया जाएगा।

सौर पंप योजना का लाभ

सौर सिंचाई योजना में हिमाचल प्रदेश सरकार छोटे और सीमांत किसानों को पंप सेट खरीद पर 90 प्रतिनिधि वित्तीय सहायता देगी। हिमाचल सरकार किसानों के छोटे और सीमांत श्रेणी/किसान विकास संघ/पंजीकृत निकाय के किसान समूह को सोलर पंप सेट पर 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता देगी।

जरुरी दस्तावेज

हिमाचल प्रदेश में निवास का स्थाई प्रमाण पत्र आधार कार्ड बैंक अकाउंट जमीन के दस्तावेज वोटर आईडी

कृषि योजनाओं का लाभ चाहिए तो मिशन रीव से करें संपर्क
अब आसान हुई खेतों और बागीचों की देखभाल

टीम रीव, बिलासपुर

सरकार ने प्रदेश में कृषि के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। लेकिन गांव के किसान जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। किसानों की इसी समस्या को सुलझाने के लिए मिशन रीव की ओर से कृषि के विकास को लेकर विशेष पहल की जा रही है। अगर गांव के किसानो को कृषि से संबंधित किसी भी योजना की जानकारी प्राप्त करनी है तो वह मिशन रीव से प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही योजनाओं का लाभ लेने में भी मिशन पूर्ण सहयोग देगा।

अभी तक मिशन रीव के माध्यम से किसानों को सोलर स्प्रे पंप, उच्च किस्म के फसलों के बीज, फूलों के बीज उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए सरकार की सोलर पंप योजना का लाभ गांव के लोगों तक पहुंचाने में मिशन रीव सहयोग कर रहा है।

प्रदेश के अन्य जिलों की तरह जिला बिलासपुर में भी किसानों को इस योजना का लाभ लेने में सहयोग किया जाएगा।

क्या है सौर पंप योजना

साल 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप सेट खरीदने पर 90 से 100 फीसदी तक सब्सिडी देने का फैसला किया है।

कृषि और बागवानी उपज बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में 20 करोड़ रुपये से सौर पंप योजना की शुरुआत की है। सौर पंप योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2018 से की गयी है।

इसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप खरीदने पर 90-100 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। योजना के मुताबिक अगर किसान अकेले पंप लगवाना चाहता है तो पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से 90 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है जबकि समूह बनाकर पंप लगवाने और पानी के स्त्रोत का प्रावधान होने पर 100 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है।

दरअसल किसान अब तक डीजल या बिजली से चलने वाले पंप से फसलों की सिंचाई करते हैं। इससे कृषि की लागत बढ़ती है। बिजली से चलने वाले सिंचाई प्रोजेक्ट पर भी लागत अधिक आती है। अब सौर पंप योजना से प्रदेश के दस लाख किसानों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत सौर पंपों से सिंचाई के लिए पानी को उठाया जाएगा।

जुब्बल में मृदा जांच से लाभान्वित होंगे किसान
मृदा जांच शिविर में 12 तरह के मृदा परीक्षण होंगे उसी आधार पर रीव जैविक खाद भी रहेगी उपलब्ध

द रीव टाइम्स ब्यूरो :

मिशन रीव (आईआईआरडी) के सौजन्य से शिमला ज़िले के जुब्बल में एक विशाल मृदा जांच शिविर का आयोजन कर रहा है। इसके लिए मिशन की ओर से टीम जुब्बल के लिए रवाना हुई। जुब्बल में किसानों की मांग पर मृदा जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर मे आसपास के गांव के लोग भाग लेंगे।

मिशन रीव से टीम प्रतिनिधि दीपा ने बताया कि किसानों के खेतों से नमूने लेकर प्रत्येक नमूने के 12 टैस्ट किए जाऐंगे। इसके लिए रीव सदस्यों को अलग दाम पर तथा जो लोग सदस्य नहीं है, उन्हें अलग दाम पर ये सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ किसानों को मृदा परीक्षण का परिणाम भी साथ ही दिया जाऐगा। जांच के बाद आने वाले परिणामों के आधार पर रीव जैविक खाद की जानकारी दी जाएगी। यानि जिन पोषक तत्वों की खेत की मिट्टी में कमी होगी, रीव जैविक खाद उसी आधार पर तैयार होगी।

रीव जैविक खाद पर भी रीव के प्रतिनिधि लोगों को जानकारी प्रदान करेंगे तथा इसका वितरण भी करेंगे।

ऊना में 20 हजार किलो जैविक खाद तैयार

टीम रीव, ऊना

मिशन रीव के तहत प्रदेश के हर जिले में ग्रामीणों को खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऊना में भी जैविक खाद लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने का जरिया बनता जा रहा है। गगरेट में पिछले दो सप्ताह के भीतर करीब 20 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए जिसमें 50 से अधिक लोगों को जैविक खाद तैयार करने की विधि बताई गई। अभी तक ऊना में 20 हजार किलो खाद तैयार की गई। उल्लेखनीय है कि इस खाद को तैयार करने के लिए जीरो बजटिंग खेती के तहत आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की ओर से गांव गांव जाकर किसानों और बागवानों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आईआईआरडी के प्रतिनिधियों की निगरानी में गांव वालों से खाद तैयार करवाई गई और खाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया गया है। संस्था के इस प्रयास की ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि खाद बनाना तो आसान है पर उसकी बिक्री अभी तक मुश्किल थी लेकिन आईआईआरडी ने इसे आसान बना दिया है। जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण देकर गांव के लोगों को व्यवसाय का भी अवसर दिया जा रहा है।

- **जैविक खाद के लाभ**
- भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है।
- सिचाई अंतराल में वृद्धि होती है।
- रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है।
- फसलों की उत्पादकता में वृद्धि।

मिट्टी की दृष्टि से लाभ

- जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है।
- भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती हैं।
- भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा।

पर्यावरण की दृष्टि से

- भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है।
- मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण मे कमी आती है।
- कचरे का उपयोग, खाद बनाने में, होने से बीमारियों में कमी आती है।
- फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि
- अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता का खरा उतरना।

शिमला में 20 हजार किलो खाद तैयार
मिशन रीव ने ग्रामीणों को दिया प्रशिक्षण
खाद की बिक्री के लिए बाजार भी कराया उपलब्ध

टीम रीव, शिमला

देश में हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमे 89.96 प्रतिशत आबादी (Census 2011) ग्रामीण क्षेत्र में रहती है हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुख्य साधन कृषि आधारित है। प्रदेश में पिछले काफी समय से जैविक खेती को लेकर योजनाएं बन रही है लेकिन अधिकतर किसानों को अभी जैविक खेती की पूरी जानकारी नहीं है। इस समस्या का समाधान करके प्रदेश को जैविक राज्य बनाने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान शिमला (आईआईआरडी) मिशन रीव के तहत अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। मिशन रीव के तहत प्रदेश के गांवों में किसानों और बागवानों को जैविक खाद बनाने का निशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। इतना ही नहीं किसानों को जैविक खाद बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि जिला शिमला में ही किसानों ने मिशन रीव के सहयोग से 20 हजार किलो जैविक खाद तैयार कर ली है और अब वह मिशन रीव के माध्यम से इसकी बिक्री करके आय प्राप्त करने की तैयारी में है। यह पहली बार है कि कोई संस्था गांव के लोगों को उन्हीं के घरद्वार पर रोजगार के साथ साथ व्यवसाय शुरू करने का भी अवसर प्रदान कर रही है। इस काम को सिरे चढ़ाने के लिए आईआईआरडी की ओर से मिशन रीव के तहत पंचायतों में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती की गई है। संस्था के ये प्रतिनिधि गांवों में ही किसानों और बागवानों जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन प्रतिनिधियों को आईआईआरडी शिमला में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। संस्था के इस प्रयास की ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि खाद बनाना तो आसान है पर उसकी बिक्री अभी तक मुश्किल थी लेकिन मिशन रीव ने इसे आसान बना दिया है। आईआईआरडी के प्रबंधक निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा का कहना है कि हिमाचल का विकास तभी संभव है जब गांव के लोगों के पास रोजगार और व्यवसाय के अवसर होंगे। जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण देकर गांव के लोगों को व्यवसाय का भी अवसर दिया जा रहा है।

कैसे बनती है जैविक खाद

आईआईआरडी ने एक ऐसे बैक्टिरिया का उपयोग किया जिसको गोबर अथवा अन्य अपशिष्ट पदार्थों मे मिलाकर जैविक खाद तैयार की जाती है। यह तकनीक National Centre for Organic Farming (NCOF) जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत है, द्वारा सामने लाई गई है जिसे किसानों तक गांव में मिशन रीव पहुंचाने का कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह है कि यह प्रचलित अन्य किसी भी प्रकार की खादों में सबसे कम समय में तैयार होती है। साथ ही गुणवत्ता के मापदंडों पर भी यह औरों से आगे हैं। इसे लगभग 30 से 40 दिनों के बीच तैयार कर लिया जाता है। इसका एक मुख्य गुण यह है कि यह ज़मीन के अंदर जाकर मिट्टी के पौष्टिक तत्वों की गुणवत्ता को बढ़ा देता हैं और ज़मीन को उपजाऊ बनाता है।

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न ज़िलों के लिए रीव जैविक खाद को भिजवाते मिशन रीव के प्रतिनिधि

द रीव टाइम्स पहुच रहा है गांव-गांव मिल रही है सराहना

मृदा परीक्षण से फसलों की पैदावार में होगा सुधार

टीम रीव, हमीरपुर

प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए ऑर्गेनिक खाद के बाद एक और अच्छी खबर है। आईआईआरडी मिशन रीव के तहत गांवो में मृदा परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहा है। इसके लिए प्रशिक्षण आईआईआरडी शिमला में दिया गया है। सभी जिलों में मृदा परीक्षण लैब स्थापित करने की प्रकिया जारी है। लैब में मृदा परीक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस मशीनें स्थापित की जा रही है। वर्तमान में जिला शिमला में किसानों मृदा परीक्षण की सुविधा दी जा रही है। अब अगले चरण में हमीरपुर में किसानों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही किसानों को जैविक खाद बनाने का परीक्षण भी दिया जाएगा।

इसके लिए भी पहले चरण में विशेषज्ञों को साथ लेकर किसानों के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद उनसे जांच के लिए मृदा सैंपल एकत्र किए जाएंगे। रिपोर्ट के आधार पर अगर किसी पोषक तत्व की कमी पाई जाती है तो इसे दूर करने में भी मिशन रीव किसानों की पूरी मदद करेगा। किसानों की मांग के आधार पर उन्हें जैविक खाद उपलब्ध कराई जाएगी जो खास तौर पर मृदा की प्रकृति के आधार पर तैयार किया जाता है।

मृदा परीक्षण क्यों?

मृदा पोषक तत्वों का भंडार है। पौधों को सीधे खड़ा रहने के लिए सहारा देती है। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता है।

मुख्य तत्व

कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम।

मृदा परीक्षण के उद्देश्य

- मृदा की उर्वरा शक्ति की जांच करके फसल व किस्म विशेष के लिए पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा की सिफारिश करना तथा यह मार्गदर्शन करना कि उर्वरक व खाद का प्रयोग कब और कैसे करें।
- मृदा में लवणता, क्षारीयता तथा अमलीयता की समस्या की पहचान व जांच के आधार पर भूमि सुधारकों की मात्रा व प्रकार की सिफारिश कर भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाने में योगदान देना और फलों के बाग लगाने के लिए भूमि की उपयुक्तता का पता लगाना।
- किसी गांव, विकास खंड, तहसील, जिला, राज्य की मृदा की उर्वरा शक्ति को मानचित्र पर प्रदर्शित करना तथा उर्वरकों की आवश्यकता का पता लगाना। इस प्रकार की सूचना प्रदान कर उर्वरक निर्माण, वितरण एवं उपयोग में सहायता करना।
- **प्रयोगशाला में मृदा की जांच**
- मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले मृदा का नमूना लिया जाता है। इसके लिए जरूरी है की मृदा का नमूना पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। यदि मृदा का नमूना ठीक ढंग से नहीं लिया गया हो और वह मृदा का सही प्रतिनिधित्व न कर रहा हो तो भले ही मृदा परीक्षण में कितनी ही सावधानियां क्यों न बरती जाएं, उसकी सिफारिश सही नहीं हो सकती। खेत की मृदा का नमूना पूरी सावधानी से लेना चाहिए

सोलन में जैविक खाद बदल रही लोगों की आर्थिकी

मिशन रीव के तहत सोलन की विभिन्न पंचायतों में जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण मिशन रीव के तहत दिया जा रहा है। इतना ही नहीं अगर कोई जैविक खाद बनाकर उसकी बिक्री करना चाहता है तो आईआईआरडी की ओर से उसे वह खाद खरीद कर मुनाफा कमाने का अवसर भी दिया जा रहा है। सोलन में सौ से अधिक किसानों को जैविक खाद बनाने का निशुल्क प्रशिक्षण मिशन रीव के तहत दिया गया है। लोग मिशन रीव के इस प्रयास से काफी खुश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अभी तक जैविक खाद बनाकर अपने खेतों में इस्तेमाल की। इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब लोग अपने खेतों के साथ साथ बिक्री के लिए भी जैविक खाद तैयार करने में जुटे हैं। अभी तक सोलन में विभिन्न किसानों की ओर से तैयार जैविक खाद को मिशन रीव के तहत बाजार उपलब्ध कराया जा चुका है। सोलन के किसानों द्वारा तैयार खाद को मिशन रीव के माध्यम से विभिन्न जिलों में भेजा जा रहा है। ये खाद किसानों द्वारा खासतौर पर बाजार में बिक्री के लिए तैयार की गई है।

किसानों का कहना है कि मिशन रीव के प्रतिनिधियों ने गांव के लोगों को इसका निशुल्क प्रशिक्षण देकर बेहतरीन कार्य किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि लोगों को प्रशिक्षण लेने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता और न ही सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

मिशन रीव के अंतर्गत पूरे हिमाचल में रीव जैविक खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई गई है। इसके प्राप्त करने लिए इन दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें .... 9459584566 और 8219175636, साथ ही आप हमारी वेबसाइट : missionriev.in/www.iirdshimla.org पर लॉगइन कर अधिक जानकारी ले सकते हैं

पूर्ण जैविक हिमाचल की ओर बढ़ते क़दम....

...रीव जैविक खाद

20रू. किलो / 40 किलो का कट्टा उपलब्ध है

Parameter	Percentage
PH	7-8
Organic carbon	7.36 - 9
Nitrogen	1.69 - 2
Phosphorus	0.75 - 1
Potassium	1.17 - 1.50
Sulphur	0.042 - 0.70
Zinc	0.0053 - 0.0075
Iron	0.14 - 0.30
Copper	0.0011
Calcium	2.2 - 3
Magnesium	1.03 - 1.20
Boron	0.0012
Manganese	0.0097
Calorific Value	219.96

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

सफलता भरा एक वर्ष.... स्वास्थ्य

हिमाचल में ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना आज भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कई महत्वकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को आज भी शहरों की दौड़ लगानी पड़ती है, अस्पताल में लंबी कतारों पर खड़ा होना पड़ता है। ऐसे में मरीजों का मर्ज अक्सर दोगुना हो जाता है। जेब पर भी यह थकाऊ प्रक्रिया भारी पड़ती है। मिशन रीव ने लोगों की इस समस्या का निवारण करने के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाओं में करीब एक साल पहले स्वास्थ्य डिविजन शामिल किया। इस डिविजन का एकमात्र उद्देश्य है गांव के लोगों को उनके घरद्वार पर कम खर्चे पर बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। गांव के लोगों का कहना है कि एक छोटे से टेस्ट कराने के लिए शहरों की दौड़ लगानी पड़ती है। अस्पताल की लंबी कतारों में खड़े-खड़े पूरा दिन निकल जाता है। दवाईयां का खर्च इतना कि सारा बजट बिगड़ जाता है। आम आदमी की इस समस्या का समाधान करने के लिए मिशन रीव के तहत प्रदेश के विभिन्न गांवों में जनऔषधि केंद्र खोलने का जिम्मा लिया गया। इन केंद्रों में मरीजों को बेहद कम दामों पर उच्च गुणवत्ता की दवाईयां मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं लोगों को बेसिक टेस्ट घर पर ही कराने की सुविधा भी मिशन के तहत दी गई। इसके अलावा ऐसे कई उदाहरण है जब मिशन रीव ने बेहद मुश्किल परिस्थितियों में लाहौल - स्पीति, किन्नौर और चंबा के जनजातिय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई। मिशन रीव के प्रतिनिधियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को ड्रिप, दवाईयां और टेस्ट की सुविधा उनके घर तक पहुंचाई। आज भी ये लोग उस कठिन समय में मिशन रीव की ओर से दी गई सेवाओं के लिए धन्यवाद करते हैं।

जनऔषधि केंद्र : स्वास्थ्य में मील का पत्थर

गांव के लोगों को कम दाम पर उच्च गुणवत्ता की दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए 15 जुलाई 2018 को प्रदेश में जनऔषधि केंद्र खोलने का सिलसिला आईआईआरडी शिमला से शुरू हुआ। इस शुरूआत के साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और अध्याय जुड़ गया। उस दौरान तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य और वर्तमान मुख्यसचिव हिमाचल प्रदेश सरकार बीके अग्रवाल ने आईआईआरडी कार्यालय से पांच जनऔषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। इसमें मंडी में भगरोटू और छतरी, कांगड़ा में नूरपुर और पालमपुर तथा हमीरपुर का जाहू केंद्र शामिल है। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनऔषिधि केंद्र खोले गए। इनमें चंबा के दूरदराज के इलाकों को भी प्राथमिकता दी गई। इसी तरह कुल्लू के हाथी थान समेत प्रदेश के कई स्थानों जनऔषिधि केंद्र खोले गए।

जब चंबा के दूरदराज गांव तक पहुंचाई गई स्वास्थ्य सुविधा...

द रीव टाइम्स, चंबा

लंबी कतारों में घंटो खड़े रहना, फिर एक टेस्ट आज हो गया तो दूसरे के लिए अगले दिन जाना। अपने जीवन के 80 बसंत दे चुके चंबा के दूरदराज के गांव शीलाघराट के थोलू राम की ये बातें इस हकीकत को जानने के लिए काफी है कि हिमाचल के गांवों में आज भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल में थोलू के जैसे ही सैंकड़ों लोग है जो इसलिए अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते और चाहकर भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन पिछले एक साल में ये तस्वीर काफी हद तक बदली मिशन रीव ने। बहरहाल, मिशन रीव प्रतिनिधि जब थोलू राम के घर पर पहुंचे तो प्रतिक्रिया कुछ युं थी, आप कौन है, मैं अस्पताल नहीं जा सकता, मैं घर में ही ठीक हूं। लेकिन जब मिशन रीव स्वास्थ्य सेवक ने बताया कि हम आपके टेस्ट कराने की व्यवस्था आपके घर पर कर देंगे, दवाई चाहिए तो वो भी लाकर घर पर देंगे तो 80 साल की बुढ़ी आंखों में हल्की चमक आ गई, झुर्रियों के बीच होंटों पर हल्की मुस्कुराहट के बीच जवाब आया, तब तो ठीक है बेटा।

बुजुर्गों की घर पर स्वास्थ्य जांच...

टीम रीव, सोलन

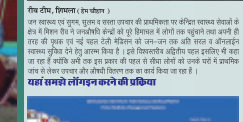

मिशन रीव के तहत लोगों को उनके घर पर ही टेस्ट सुविधा प्रदान की गई। सोलन, कांगड़ा, शिमला, ऊना समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी कई तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उनके घर पर उपलब्ध कराई गई। इससे उन लोगों को काफी लाभ हुआ जो बीमारी के कारण या बुजुर्ग होने के कारण लंबा सफर तय कर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। घर पर ही टेस्ट सुविधा मिलने से गांव में लोगों को काफी राहत मिली। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बेसिक टेस्ट कराने के लिए शहरों में जाकर अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़े। टेस्ट करवाने के बाद लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक हो गए है।

गांव के बुजुर्गों का कहना है कि मिशन रीव के तहत टेस्ट सुविधा घर पर ही मिली। पहले एक साधारण टेस्ट कराने के लिए निजी क्लीनिक या अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते थे। बसों में भीड़ के बीच बाजार पहुंचना और टेस्ट के लिए लाइनों में लगना और उसके बाद रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार। यह सारी प्रक्रिया मरीज के मर्ज को और बढ़ा देती है। लेकिन मिशन रीव ने इन सारी समस्याओं का हल कर दिया। स्वास्थ्य सेवकों घर में आकर ही टेस्ट और बाजार से दवाईयां लाने जैसे काम आसानी से कर दिया।

जब सरला के लिए जीवन रक्षक बना मिशन रीव

टीम रीव, किन्नौर

बात करीब एक साल पहले की है। बरसात का मौसम पूरे जोरों पर था। मौसम बेहद खराब था। लगातार बारिश से रास्ता टूट गया था । ऐसे में अस्पताल पहुंचना नामुनकिन था। किन्नौर के कल्पा ब्लॉक की थेमंगरंग पंचायत की सरला की तबीयत डिहाइड्रेशन के कारण लगातार बिगड़ती जा रही थी। जब डाक्टर से किसी तरह संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत मरीज को ड्रिप लगाने की सलाह दी। लेकिन खराब मौसम के बीच ड्रिप घर तक लाना किसी चुनौती से कम नहीं था। ऐसे में मिशन रीव के प्रतिनिधी ने जब सरला के घर ड्रिप पहुंचाई तब कहीं जाकर सरला के परिवार ने राहत की सांस ली। सरला ने ठीक होने के बाद मिशन रीव के साथ अपने अनुभव को कुछ इस तरह साझा किया, मुझे तो लग रहा था कि मैं अब एक महीना बिस्तर से नहीं उठ पाउंगी। मौसम खराब होने के कारण रास्ता टूट गया तो अस्पताल जाना भी मुश्किल था। लेकिन जब मिशन प्रतिनिधि ने ड्रिप का इंतजाम घर पर ही कर दिया तो मेरी जान में जान आई। अब में ठीक हूं और मिशन रीव का धन्यवाद करती हूं कि जब मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी तो मिशन रीव के प्रतिनिधि ने हमारी सहायता की। सरला की ही तरह किन्नौर और लाहुल स्पीति के दूर दराज के गावों में मिशन रीव लोगों के जीवन को न केवल आसान बनाने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें वह सभी सेवाएं प्रदान करने में लगा है जिसके लिए उन्हें मीलों दूर का सफर तय करना पड़ता है।

आईआईआरडी में खुला रीव क्लीनिक

द रीव टाइम्स, शिमला

ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आईआईआरडी शनान में एक साल पूर्व रीव क्लीनिक खोला गया। इस क्लीनिक में विभिन्न तरह के टेस्ट कराने की सुविधा के साथ ही स्वास्थ्य परामर्श भी लोगों को दिया जा रहा है। इस क्लीनिलक से संजौली मल्याना, शनान व पंथाघाटी के आसपास के लोगों को काफी लाभ हो रहा है। शनान में रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले उन्हें ब्लड प्रेशर चैकअप करने के लिए भी डीडीयू या संजौली जाना पड़ता था। लेकिन अब शनान में ही टेस्ट की सुविधा मिलने से काफी आराम है। रीव क्लीनिक के साथ ही यहां पर जनऔषधि केंद्र भी है। इस केंद्र में दवाईयां बाजार से कम कीमतों पर उपलब्ध हैं।

सामार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

सफलता भरा एक वर्ष.... घर द्वार सेवाएं

मिशन रीव से आसान हुई लोगों के जीवन की राह : बीते एक साल के दौरान मिशन रीव ने न केवल कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीण लोगों का सहयोग किया बल्कि रोजमर्रा की छोटी - छोटी जरूरतों को पूरा करने में भी मिशन एक सहयोगी के तौर पर हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहा। ऐसे अनेक उदाहरण है जब गांव के लोगों को शहर तक पहुंचने में परेशानी होती थी और जरूरत का सामान लेने बाजार नहीं जा सकते थे। ऐसे में मिशन रीव के प्रतिनिधियों ने गांव के लोगों को उनके घर पर लाकर यह सामान पहुंचाया जिससे गांव के लोगों की राह आसान हो गई। घर तक बाजार से राशन पहुंचाने से लेकर खेतीबाड़ी और पशुध की देखभाल से लेकर मिशन रीव गां के लोगों के साथ हर कदम पर खड़ा रहा। गांव में यूं तो लोग खेतीबाड़ी को ही अपनी आय का मुख्य साधन मानते हैं लेकिन कुछ युवा खेतीबाड़ी के साथ - साथ कुछ अन्य व्यवसाय करने के भी इच्छुक होते हैं। मिशन रीव ने इन युवाओं के सपनों को पंख देने का काम किया और कइयों को अपना व्यवसाय शुरू करने में भरपूर मदद भी की। इसमें एक दुकान खोलने से लेकर अन्य व्यवसाय शुरू करने जैसे कई कार्य शामिल है। दरअसल गांव के लोगों के लिए सबसे मुश्किल होता है किसी भी काम को शुरू करने से पहले की दस्तावेजी औपचारिकताओं को पूरा करना। मिशन रीव ने इस काम को भी पूरी जिम्मदारी से निभाया और गांव के लोगों के जीवन की राह आसान की। यह काम उन्हें उनके घर पर पूरे करके दिए गए।....

हर छोटे - बड़े काम को दिया अंजाम : मिशन रीव के तहत प्रदेश के विभिन्न गांवों में लोगों की मदद की जा रही है। बात बाजार से राशन लाने की हो या दस्तावेजी औपचारिकताओं को पूरा करने की हो या अन्य किसी कार्य को पूरा करने की, हर जिम्मेदारी को मिशन रीव बखूबी निभा रहा है। शिमला, सोलन, ऊना सहित अन्य जिलों के गांवों में लोग विभिन्न सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि मिशन रीव से गांव के लोगों का जीवन आसान हो गया है। बात लोन लेने की हो, किसी काम को करने के लिए अन्नापति प्रमाण पत्र लेना हो या बिल जमा कराने जैसे रोजमर्रा के काम हो, सभी मिशन रीव के तहत आसानी से हो जाते हैं। शिमला, सोलन व ऊना में कई ऐसे उदाहरण है जब लोगों के पेजिदा काम भी घर बैठे हो गए। जिला की गुगलैहड़ पंचायत में मिशन रीव के तहत लोगों ने लोन प्राप्त करने में सहयोग प्राप्त किया तो वहीं कई लोगों ने डेयरी और फुटवेयर जैसे व्यवसाय भी मिशन रीव के सहयोग से स्थापित किए। राजेंद्र सिंह गुगलैहड़ पंचायत के निवासी है। उन्होंने बताया कि वह काफी समय से लोन लेना चाहते थे लेकिन इसके लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि संबंधित दस्तावेजों को जुटाने का न तो उनके पास समय था और न ही यह पूरी तरह पता था कि लोन कहां से कैसे प्राप्त करना है। इसके बाद मिशन रीव प्रतिनिधि से बात की। मिशन प्रतिनिधि ने स्वंय पूरी औपचारिकताएं पूरी की और उन्हें खादी लोन मिल गया। इसके लिए न तो उन्हें दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े और न ही अन्य कोई खास परेशानी झेलनी पड़ी। इसके अलावा मिशन रीव के तहत 200 से अधिक लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में मदद की गई तो कई लोगों को व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान नहीं क्योंकि इसके लिए कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। लेकिन मिशन रीव के तहत अब सब कार्य आसानी से हो जाते हैं। इसी तरह प्रदेश के दूसरे जिलों में भी मिशन की सेवाएं निर्बाध जारी है।

विकासात्मक योजनाओं को गांव तक पहुंचा रहा मिशन रीव : हिमाचल में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को बाजार तक पहुंचने के कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी जानकारी के अभाव में लोगों तक नहीं पहुंच रहा। लोगों की इसी समस्या को दूर करने के लिए मिशन रीव के तहत लोगों की जरूरतों को पहचाना गया और उनकी जरूरतों को पूरा भी किया जा रहा है। इसके लिए मिशन रीव के तहत पंचायत में तैनात आईआईआरडी के प्रतिनिधि विशेष शिविरों का आयोजन कर रहे है। बीते वर्ष बिलासपुर की पडयालग, दाबला, कासरू, बेरीराजदियां, हंबोट पंचायत में इसी तरह के शिविरों का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला मंडल, स्वंय सहायता समूह और स्थानीय लोगों ने बढ़ - चढ़कर भाग लिया। इस दौरान मिशन रीव की सेवाओं के साथ - साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी गई। रीव प्रतिनिधि ने जब लोगों से पूछा की उन्हें सरकारी योजनाओं की कितनी जानकारी है, तो लोगों ने साफ कहा कि योजनाएं तो पता है लेकिन इनका लाभ कैसे और कहां से मिलेगा, इसके बारे में नहीं पता। इसी तरह कृषि संबंधि योजनाओं के बारे में भी लोगों ने मिशन रीव के प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त लोगों को मिशन रीव के तहत उपलब्ध कराए जा रहे एनीमल फूड सप्लीमेंट की जानकारी दी गई। इसके साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह का सामान ग्रामीणों के घरों तक मिशन रीव के प्रतिनिधियों द्वारा पहुंचाया गया। इस दौरान लोगों ने पशुधन के माध्यम से आर्थिकी मजबूत करने पर चर्चा की और मिशन रीव के तहत एनीमल फूड सप्लीमेंट उपलब्ध कराने की मांग की। इसके बाद उन्हें सप्लीमेंट भी उपलब्ध करवाया गया हैं जिसके काफी बेहतर परिणाम सामने आए हैं। पशुपालकों का कहना है कि मिशन रीव के तहत एनीमल फूड सप्लीमेंट से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और दूध की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है।

घर-घर जाकर हो रहा आवश्यकता आकलन, गांव के लोगों की जरुरतें पहचान रहा मिशन रीव : मिशन रीव के तहत समस्त सेवाओं की लोगों तक उपलब्धता ही मिशन का ध्येय है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य सदस्यों की आवश्यकताओं का आकलन कर रहा है। इस आकलन के पीछे सदस्यों एवं उनके समस्त परिवारजनों की एक - एक व्यक्तिगत पारिवारिक, सामाजिक समस्याओं की पहचान करना एवं उनके समाधान के लिए प्रयास करना है। इसके लिए मिशन प्रतिनिधियों की ओर से लोगों के घरों में जाकर उनकी आवश्यकतों का आंकलन किया जा रहा है। हर जिले में करीब एक हजार से अधिक लोगों की आवश्यकता का आकलन उनके घर पर जाकर ही किया जा चुका है। इतना ही नहीं प्राथमिकता आधार पर लोगों की आवश्यकता को पूरा करने की प्रक्रिया भी जारी है। सदस्यों की आवश्यकता आकलन के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया को पूरी करने में मिशन रीव के प्रतिनिधि लोगों की पूरी सहायता करते हैं। फार्म भरने से लेकर आकलन की पूरी प्रक्रिया मिशन प्रतिनिधि पूरी करते हैं।

आवश्यकता आकलन का भिन्न वर्गो में विभाजन : आवश्यकता आकलन को कुल 8 वर्गो में विभाजित किया गया है। इन वर्गों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि हर क्षेत्र से संबन्धित समस्या अथवा आवश्यकता इसमें शामिल की जा सके। इतना ही नहीं अलग से सुझाव देने के लिए भी विकल्प रखा गया है। जहां संयुक्त रूप से आवश्यकता आकलन किया जाता है वहीं यदि कोई अलग

से अपनी समस्या साझा करना चाहे तो उसकी भी पूरी सहायता रीव टीम की ओर से की जाती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रश्नावलियों से लोगों की आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है। इसमें सभी की दैनिक एवं मूलभूत समस्याओं को शामिल किया गया है। किसान से संबंधित प्रश्न किसान की समस्त समस्याओं को से जुड़े हैं तो वहीं विद्यार्थी अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग के लिए उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के साथ ही प्रश्नावली तैयार की गई है।

आवश्यकता आकलन के पर आधार घर - द्वार सेवाएं
रीव के फेसिलिटेटर गांव में आवश्यकता आकलन को ही आधार बनाकर सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कर रहे हैं। समस्या पंचायत स्तर की हो, खण्ड स्तर की हो, ज़िला अथवा सरकार के स्तर की हो, मिशन रीव के तहत हर स्तर पर सहयोग दिया जा रहा है।

लौहाल - स्पीति में लोगों को किया जागरुक
मिशन रीव लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही उन्हें उन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दे रहा है जो सरकार की ओर से खास तौर उनके लिए बनाई गई है। इस बात को सरकारी अधिकारी भी मानतें है कि जानकारी के अभाव में अधिकतर योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इस खाई को पाटने के लिए लाहौल स्पीति के दूर दराज के गांवों में मिशन रीव के प्रतिनिधियों की ओर से विशेष तौर पर गांवों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत काजा व अन्य ब्लॉक में भी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को मिशन रीव के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं, मिट्टी जांच परीक्षण व अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही काजा के लोगों को उन सरकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया जो खास तौर पर जनजातीय क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है। लोगों यह भी जानकारी दी गई कि वह कैसे आसानी से इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

भारत के स्मार्ट गांव के लिए मिशन रीव हो सकता है मॉडल
दिल्ली के प्रगति मैदान में मिशन रीव पर प्रस्तुतिकरण

द रीव टाइम्स : हेम राज चौहान

दिल्ली के प्रगति मैदान में एग्जिबिशन ईंडिया ग्रुप की वार्षिक सम्मेलन में स्मार्ट विलेजिज पर मिशन रीव के मॉडल को प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तुतिकरण को रीव के प्रणेता डॉ. एल सी शर्मा ने देशभर से आए प्रतिभागियों के समक्ष रखा। स्मार्ट सिटी के बाद अब स्मार्ट गांव पर भारत सरकार प्रयास कर रही है। इसी पर चर्चा एवं उद्बोधन के लिए देश भर से विभिन्न संस्थाओं एवं एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने अपना प्रस्तुतिकरण किया। आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा ने मिशन रीव के मॉडल को प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि जब तक गांव स्मार्ट नहीं होंगे तब तक देश का विकास यर्थात् पर नहीं आ सकता है। स्मार्ट गांव के लिए लोगों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। मिशन रीव इसी मॉडल का नाम है। जो लोगों की दुःख तकलीफ और उन्हें सहयोग देने की जीवंत पद्धति पर सेवाऐं दे रहा है। भारत को स्मार्ट गांव बनाने में सबसे अधिक कारगर मिशन रीव मॉडल ही हो सकता है। उन्होंने मिशन रीव में आवश्यकता आकलन को सबसे अधिक प्रभावी बताया और कहा कि आवश्यकता आकलन के माध्यम से गांव-गांव में घर-घर तक एक-एक आदमी की आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है जिससे उनकी समस्याओं और प्राथमिकताओं को सामने लाया जाता है। उसी आधार पर मिशन रीव ऐसोसियेट अपनी सेवाऐं देते हैं। इसका मूल यही है कि गांव की बेहतरी और आम इंसान की जीवन शैली में बदलाव लाकर लोगों को उनकी समस्याओं से दूर कर उन्हें अपने राष्ट्र एवं व्यक्तिगत निर्माण में सहयोग देने के लिए उन्मुक्त भाव से स्वतंत्रता मिले। गौरतलब है कि मिशन रीव पर डॉ० एल सी शर्मा ने देश भर में इसकी सार्थकता को साबित किया है। इसके अलावा यूएन में भी मिशन रीव का डंका बज चुका है जहां इस मॉडल पर न केवल चर्चा हुई बल्कि इस मॉडल को कई अन्य देशों ने भी सराहा है।

पांच सौ से अधिक लोगों का स्वास्थ्य जांचा

टीम रीव, कुल्लू

अन्य जिलों की तरह ही कुल्लू में भी स्वास्थ्य स्लेट लोगों के स्वास्थ्य देखभाल में अहम साबित हो रही है। स्वास्थ्य स्लेट के माध्यम से लोगों के घरों पर ही उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट कराने के बाद अगर कोई चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहते हैं तो वह सुविधा भी उन्हें दी जा रही है। स्वास्थ्य स्लेट से अभी तक करीब पांच सौ लोगों के स्वास्थ्य की जांच उनके घर पर ही की जा चुकी है।
लोगों के घरों के अलावा अलग से जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी शिविर के दौरान लोगों के टेस्ट करने के साथ-साथ उन्हें मिशन रीव की ओर से दी जा रही सेवाओं की भी जानकारी दी गई। लोगो ने बताया कि उन्हें काफी अच्छा लग रहा है कि घर पर ही टेस्ट हो रहे हैं और उन्हें अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं।

लोगों को दी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी

टीम रीव, हमीरपुर

रिवालसर में मिशन रीव के स्वास्थ्य सेवक की ओर से स्थानीय लोगों के घरों में जाकर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। इसके साथ ही उन्हें मिशन रीव के तहत उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सेवाओं की भी जानकारी दी जा रही है। हैल्थ टेस्टिंग मशीन स्वास्थ्य स्लेट के बारे में जानकारी दी। मिशन रीव स्वास्थ्य जांच के साथ साथ घर द्वार पर सस्ती दवाएं भी उपलब्ध करवा रहा है, इस बारे में भी लोगों को बताया गया।
स्वास्थ्य स्लेट से हमीरपुर की विभिन्न पंचायतों में लोगों के घरों में ही जाकर टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी तक तीन सौ से अधिक लोगों के स्वास्थ्स की जांच उनके घरों पर जाकर ही की जा चुकी है। मिशन रीव की ओर से यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की ग्रामीण लोगों की ओर से प्रशंसा भी की जा रही है। लोगों का कहना है कि घर पर ही टेस्ट सुविधा से स्वास्थ्य की देखभाल आसान हो गई है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिशन रीव ने हासिल किया नया आयाम

टीम रीव, शिमला

दूर गांव से बसों में धक्के खाते हुए दूर अस्पताल तक पहुंचना, लंबी कतारों में घंटो खड़े रहना, फिर एक टेस्ट आज हो गया तो दूसरे के लिए अगले दिन जाना। अपने जीवन के 80 बसंत दे चुके चंबा के दूरदराज के गांव शीलाघराट के थोलू राम की ये बातें इस हकीकत को जानने के लिए काफी है कि हिमाचल के गांवों में आज भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल में थोलू के जैसे ही सैंकड़ों लोग है जो इसलिए अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते और चाहकर भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन पिछले छह माह में ये तस्वीर काफी हद तक बदली है मिशन रीव ने। बहरहाल, मिशन रीव प्रतिनिधि जब थोलू राम के घर पर पहुंचे तो प्रतिक्रिया कुछ यूं थी, आप कौन है, मैं अस्पताल नहीं जा सकता, मैं घर में ही ठीक हूं। लेकिन जब मिशन रीव स्वास्थ्य सेवक नरेश ने बताया कि हम आपके टेस्ट आपके घर पर ही करेंगे, दवाई चाहिए तो वो भी लाकर घर पर देंगे तो 80 साल की बुढ़ी आंखों में हल्की चमक आ गई, झुर्रियों के बीच होटों पर हल्की मुस्कुराहट के बीच जवाब आया, तब तो ठीक है बेटा।
हिमाचल के गांवों में बसने वाले हजारों लोगों के चेहरों पर ऐसी ही मुस्कुराहट लाने में मिशन रीव कामयाब रहा है। मई 2018 से गांवों में स्वास्थ्य सेवकों को स्वास्थ्य स्लेट दी गई और लोगों के घरों में ही उनके प्रारंभिक टेस्ट कराने की जिम्मेदारी सौपी गई। मिशन रीव इस काम को करने में पूरी तरह सफल रहा और महज छह माह में ही प्रदेश के विभिन्न गांवों में तीन हजार से अधिक लोगों के करीब पांच हजार बेसिक टेस्ट किए गए। ये वो टेस्ट हैं जिन्हें करवाने से कोई भी अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रारंभिक जानकरी प्राप्त कर सकता है। आंकड़ों पर गौर करें तो मई से अक्तूबर तक 12 जिलों के 3 हजार लोगों के 5 हजार टेस्ट करवाए गए। खास बात ये कि ये सभी टेस्ट लोगों के घर पर जाकर मिशन रीव स्वास्थ्य सेवकों द्वारा किए गए।

जनाऔषधि केंद्र से ग्रामीणों को राहत
खराब मौसम में भी आसानी से मिल रही दवाईयां

टीम रीव, चंबा

एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान, आईआईआरडी शिमला की एक नई पहल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में लोगों को सस्ते दामों पर दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तीन सौ जनऔषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी के तहत चंबा के तीसा में भी जनऔषधि खोला गया है। चंबा के तीसा में यह पहला जनऔषधि केंद्र है। इसके खुलने से तीसा के लोगों को अब सस्ती दवाईयों के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। खास बात यह कि चंबा इन दिनों भारी बर्फबारी की जद में है। गांव से शहरों तक पहुंचना किसी चुनौति से कम नहीं है। ऐसे में तीसा में खोला गया जनऔषधि केंद्र लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है क्योंकि मौसम खराब होने के बावजूद लोगों को इस केंद्र पर आसानी से सभी दवाईयां मिल रही है और उन्हें इसके लिए बाजार नहीं जाना पड़ रहा है। बाजार में भी अधिकतर दुकानों पर खराब मौसम के कारण सभी दवाईयां नहीं मिल पा रही, दूसरे गांवों से बाजार तक पहुंचना भी मुश्किल है। ऐसे में तीसा में खुला जनऔषधि केंद्र वहां के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है।
तीसा के लोगों का कहना है कि अभी तक उन्हें बाजार से मंहगे दामों पर दवाईयां खरीदनी पड़ती थी। कई बार तो ये दवाईयां जेब पर इतनी भारी पड़ जाती थी कि घर का पूरा बजट ही बिगड़ जाता था। लेकिन अब आईआईआरडी की ओर से प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना के तहत तीसा में सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराई जा रही है। इससे स्थानीय लोगों को काफी राहत है। तीसा में ही जनऔषधि केंद्र खुलने से इलाज सस्ता हो गया और लोगों के समय की भी बचत हो रही है।

हेल्थ कैंप में तीन सौ से अधिक का स्वास्थ्य जांचा
गांव में ही टेस्ट सुविधा मिलने से ग्रामीण खुश

सोलन, टीम रीव

लोगों को उनके घरद्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से मिशन रीव के तहत अभी तक करीब 15 स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। इनमें जहां सदस्यों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच की जा रही है वहीं अन्य लोग भी इस सेवा का लाभ ले रहे है। गांव में ही टेस्ट की सुविधा मिलने से ग्रामिणों में भी खुशी की लहर है। सोलन ब्लॉक के माझीवर पंचायत के बाशिंदों कहना है कि पहले उन्हें ब्लड प्रेशर तक की जांच के लिए शहर जाना पड़ता था लेकिन अब गांव में ही विभिन्न तरह के टेस्ट की सुविधा है। इसके चलते स्वास्थ्य का ध्यान और समय समय पर ब्लड टेस्ट कराने में आसानी हो गई है। माझीवर पंचायत की ही तर्ज पर कंडाघाट ब्लॉक की बीज़ा पंचायत, कुनिहार ब्लॉक चखेर पंचायत समेत विभिन्न स्थानों पर इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों में लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है।

हेल्थ कैंप से सैकड़ो को हो रहा स्वास्थ्य लाभ

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सोलन
मोबाईल हैल्थ सर्विसेज के तहत मिशन रीव की ओर से विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत मिशन रीव के सदस्यों के साथ साथ गैर सदस्यों को भी उनकी पंचायत में ही स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। जिला सोलन में मिशन रीव के तहत अभी तक करीब 20 स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जा चुका गांव में ही टेस्ट की सुविधा मिलने से ग्रामिणों में भी खुशी की लहर है। सोलन ब्लॉक के के बाशिंदों कहना है कि पहले उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर जैसे टेस्ट तक के लिए शहर जाना पड़ता था। अस्पतालों में टेस्ट कराने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है और उसके बाद रिपोर्ट के लिए लंबा इंजतार करना पड़ता है। अब गांव में ही विभिन्न तरह के टेस्ट की सुविधा है। इसके चलते स्वास्थ्य का ध्यान और समय समय पर ब्लड टेस्ट कराने में आसानी हो गई है। ककीरा पंचायत की ही तर्ज पर अन्य पंचायतों में विभिन्न स्थानों पर इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों में लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है।

आईआईआरडी में खुला रीव क्लीनिक
चैकअप के साथ स्वास्थ्य परामर्श भी

द रीव टाइम्स, शिमला

ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आईआईआरडी शनान में हाल ही में रीव क्लीनिक खोला गया है। इस क्लीनिक में विभिन्न तरह के टेस्ट कराने की सुविधा के साथ ही स्वास्थ्य परामर्श भी लोगों को दिया जा रहा है। इस क्लीनिलक से संजौली मल्याना, शनान व पंथाघाटी के आसपास के लोगों को काफी लाभ हो रहा है। शनान में रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले उन्हें ब्लड प्रेशर चैकअप करने के लिए भी डीडीयू या संजौली जाना पड़ता था। लेकिन अब शनान में ही टेस्ट की सुविधा मिलने से काफी आराम है। रीव क्लीनिक के साथ ही यहां पर जनऔषधि केंद्र भी है। इस केंद्र में दवाईयां बाजार से कम कीमतों पर उपलब्ध हैं।

मिशन रीव से आसान हुआ दूरदराज के गांवों में जीवन
कुल्लू में घर-घर मिल रही सेवा

टीम रीव, कुल्लू

हिमाचल में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को बाजार तक पहुंचने के कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। अधिकतर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी नहीं मिल पाती।
इसी समस्या को दूर करने के लिए मिशन रीव के तहत लोगों की जरूरतों को पहचाना गया बल्कि उनकी जरूरतों को पूरा भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में मिशन रीव के तहत पंचायत में तैनात आईआईआरडी के प्रतिनिधि विशेष शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। हाल ही में जगातसुख के भनारा गांव में इसी तरह के शिविर का आयोजन किया और लोगों को मिशन रीव के तहत उपलब्ध कराए जा एनीमल फूड सप्लीमेंट की जानकारी दी गई। इसके साथ ही लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह का सामान उनके घरों तक मिशन रीव के प्रतिनिधियों द्वारा पहुंचाया गया। इस मौके पर लोगों ने पशुधन के माध्यम से आर्थिकी मजबूत करने पर चर्चा की और मिशन रीव के तहत एनीमल फूड सप्लीमेंट उपलब्ध कराने की मांग की। इसके बाद उन्हें सप्लीमेंट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसके काफी बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि मिशन रीव के तहत एनीमल फूड सप्लीमेंट से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और दूध की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में रोजमर्रा की जरूरत का सामान जैसे साबुन, क्रॉकरी, शैंपू आदि भी लोगों को घरों तक पहुंचाया जा रहा है।

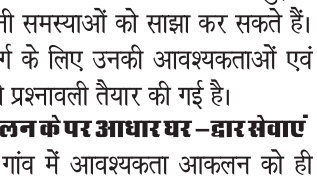

कृषि और पशुधन में हुआ सुधार

बुजुर्गो का सहारा बना मिशन रीव
घर पर ही हो रही स्वास्थ्य जांच

टीम रीव, सोलन

मिशन रीव के तहत स्वास्थ्य स्लेट से लोगों को उनके घर पर ही टेस्ट सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सोलन में भी स्वास्थ्य स्लेट से लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जांच शिविर लगाने के अलावा लोगों के घरों में जाकर भी स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इससे उन लोगों को काफी आसानी हो रही है जो बीमारी के कारण या बुजुर्ग होने के कारण लंबा सफर तय कर अस्पताल नहीं पहुंच पाते है। घर पर ही टेस्ट सुविधा मिलने से गांव में लोगों को काफी राहत है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब बेसिक टेस्ट कराने के लिए शहरों में जाकर अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। स्वास्थ्य स्लेट से टेस्ट करवाने के बाद लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक हो गए है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि मिशन रीव के तहत टेस्ट सुविधा घर पर ही मिल रही है। पहले एक साधारण टेस्ट कराने के लिए निजी क्लीनिक या अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते थे। बसों में भीड़ के बीच बाजार पहुंचना और टेस्ट के लिए लाइनों में लगना और उसके बाद रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार। यह सारी प्रक्रिया मरीज के मर्ज को और बढ़ा देती है। लेकिन मिशन रीव ने इन सारी समस्याओं का हल कर दिया है। स्वास्थ्य सेवक घर में आकर ही टेस्ट सुविधा प्रदान कर रहे हैं , जरूरत पड़ने पर बाजार से दवाईयां लाकर भी घर पहुंचा रहे है।

सोलन में स्वास्थ्य स्लेट से स्वास्थ्य देखभाल
घर पर ही टेस्ट सुविधा मिलने से ग्रामीणों को राहत

टीम रीव, सोलन

मिशन रीव के तहत स्वास्थ्य स्लेट से लोगों को उनके घर पर ही टेस्ट सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके चलते गांव में लोगों को काफी राहत है क्योंकि लोगों को बेसिक टेस्ट कराने के लिए शहरों में अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते।
स्वास्थ्य स्लेट से टेस्ट करवाने के बाद लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक हो गए है। सोलन के 65 वर्षीय दुर्गादास का कहना है कि अब उन्हें हर माह अस्पताल नहीं जाना पड़ता और उनका शुगर और बीपी का टेस्ट घर पर ही हो जाता है। इसे उन्होंने काफी राहत महसूस की है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

साइबर क्राइम से कैसे बचें महिलाऐं?

सोशल मीडिया

इन अपराधों से निपटने के लिए कानून बनाया गया है लेकिन अपनी तरफ से भी कुछ सावधानियां बरतकर महिलाएं इन समस्याओं से बच सकती हैं और बिना किसी चिंता के सोशल मीडिया पर एक्टिव रह सकती हैं। इस बारे में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते समय कुछ बातों का ख़्याल रखने की सलाह देते हैं। इनके बारे में हम यहां बता रहे हैं:

क्या करें, क्या न करें

- सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर अपनी निजी तस्वीरें डालने से बचें। उनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है।
- अगर फिर भी आप तस्वीरें डालना चाहते हैं तो अपने फेसबुक अकाउंट पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को पब्लिक न करें।
- सेटिंग्स ऐसे रखें कि आपकी फोटो आपके दोस्त या आपसे जुड़े हुए लोग ही देख पाएं। अनजान लोग उन तक न पहुंचे।
- अपने नाम के बारे में गूगल पर हमेशा सर्च करते रहें ताकि आपको पता रहे कि आपका नाम कहां पर और किस-किस वेबसाइट पर आ रहा है।
- अगर किसी गलत जगह पर या ऐसी जगह पर आपको नाम दिखाई देता है जिसकी अनुमति आपने नहीं दी है, तो उसे तुरंत हटाने के लिए

कह सकते हैं।

- अनजान लोगों को फेसबुक पर न जोड़ें। कई बार ऐसा करने से नुकसान भी हो सकता है। प्रोफेशनल लोगों को लिंकडइन पर जोड़ें, फेसबुक पर उनके साथ न जुड़ें।

वहीं, ट्विटर के ऊपर बिल्कुल भी निजी तस्वीरें न डालें। यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, यह एक ट्विटिंग प्लेटफॉर्म है।

ट्विटर पर ऐसी सेटिंग्स की जा सकती हैं कि आपकी अनुमति के बिना लोग आपको फॉलो न कर सकें। लेकिन, अमूमन लोग ऐसा करते नहीं हैं। सेटिंग्स को ज्यादा निजी करके आपका अकाउंट ज्यादा सुरक्षित रह सकता है।

आप कई बार किसी का अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं या उसकी रिपोर्ट कर देते हैं। इसके बाद ब्लॉक किया हुआ शख़्स आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच सकता लेकिन ध्यान रखें कि वो दूसरे अकाउंट से आप तक पहुंच सकता है।

ऐसे में किसी दूसरे अनजान प्रोफाइल की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारने से पहले इस बात को दिमाग में रखें।

अगर आप किसी समस्या में फंस भी जाते हैं तो घबराएं नहीं बल्कि पुलिस को इसकी जानकारी दें।

कैसे पता करें नकली अकाउंट

अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी फेसबुक अकाउंट में लड़की की तस्वीर लगी होती है लेकिन वो अकाउंट किसी लड़के ने बनाया होता है। इसी तरह नकली नाम और तस्वीर के साथ भी फेसबुक अकाउंट बना होता है।

विशेषज्ञ बताते हैं, ''ऐसे अकाउंट का पता लगाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। किसी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से पहले सामने वाले का अकाउंट अच्छी तरह देख लें।'

जितेन जैन के मुताबिक, ''ऐसे नकली अकाउंट में अक्सर सारी फोटो उसी दिन डली हुई होती हैं। वो सिर्फ तीन-चार ग्रुप्स से जुड़ा होता है और 10-15

दोस्त होते हैं। कई बार ऐसे अकाउंट में अलग-अलग लड़कियों की तस्वीरें होती हैं। तस्वीरें आपत्तिजनक तक हो सकती हैं।'

विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसा भी होता है कि प्रोफाइल पिक किसी लड़की की होती है लेकिन गैलरी में उसकी एक भी तस्वीर नहीं होती और न कोई पोस्ट होता है। इस तरह के अकाउंट से बचना ही चाहिए।

लाइक्स की चाह

सोशल स्पेस पर महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं पर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट अनुजा त्रेहन कपूर कहती हैं, ''महिलाओं को जब असल जिंदगी में उम्मीद के मुताबिक महत्व नहीं मिलता तो उसका झुकाव वर्चुअल की दुनिया की ओर ज्यादा होता है जहां उनकी तारीफ करते लोग थकते नहीं हैं। सेल्फी की ही बात करें तो इसने हमें ऐसी जगह ला दिया है कि वर्चुअल दुनिया में तो आपको लाइक मिलेंगे लेकिन असल दुनिया में आपको कोई पूछेगा भी नहीं।'

अनुजा कपूर कहती हैं, ''लाइक्स और प्रशंसा की यही चाह लोगों को तस्वीरें डालने के प्रोत्साहित करती हैं और आप अपनी निजी जानकारियां व तस्वीरें डालने का सिलसिला बढ़ा देते हैं। महिलाओं के साथ यही स्थिति होती है। उस वक्त वो ये नहीं सोच पाती हैं कि इनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है।'

अनुजा कपूर बताती हैं, ''लड़कियों के साथ हो रही घटनाएं साइबर क्राइम बढ़ने का भी हिस्सा हैं। साइबर क्राइम आपको पहचान छुपाने का मौका देता है। ये लोगों के लिए अपराध करना और आसान बना देता है। वहीं, अक्सर लोग सार्वजनिक रूप से अपनी दिनचर्या बता देते हैं। घर कहां है, कहां गए हैं और कहां जाने वाले हैं ये सब बता देते हैं। ये सामने वाले को अपराध के लिए न्यौता देने जैसा है।'

अनुजा कहती हैं कि लोगों को वर्चुअल से ज्यादा असल जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन, इसे पूरी तरह भी नहीं छोड़ा जा सकता तो सुरक्षा के लिए आ रहे नए तरीकों को अपनाएं। फिर भी कोई समस्या हो तो कानून का सहारा लेना चाहिए।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है। आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर पूछे जा सकते है।

सर्वाइकल पेन का इलाज

यह समस्या हड्डियों से जुड़ी है, जिसके होने पर कंधों, गर्दन आदि में गंभीर दर्द होता है जिसे हम सर्वाइकल का दर्द कहते हैं। यह समस्या किसी को भी हो सकती है। घंटों बैठे रहना, खराब मुद्रा, झुक कर बैठना और कई अन्य गलत आदतों की वजह से इस परेशानी का सामना बड़ी तादाद में लोगों को करना पड़ता है।

सर्वाइकल पेन के कारण

- गलत पोजीशन में सोने से आपको सर्वाइकल पेन होने लगता है।
- ज्यादातर लोगों को भारी वजन को सिर पर उठाने से सर्वाइकल पेन होता है।
- गर्दन को बहुत देर तक झुकाये रखने से भी सर्वाइकल पेन हो सकता है।
- बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठने से सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है।
- ऊंचे और बड़े तकिये का प्रयोग करने से सर्वाइकल पेन होता है।
- भारी वजन के हेलमेट डालकर बाइक राइडिंग करने से भी सर्वाइकल हो सकता है।
- गलत उठने, बैठने और सोने के तरीकों के कारण भी सर्वाइकल हो सकता है।

सर्वाइकल पेन के लक्षण

- सिर का दर्द
- गर्दन को हिलाने पर गर्दन में से हड्डियों के टिडकने के जैसी आवाज का आना।
- हाथ, बाजू और उंगलियों में कमजोरी महसूस होना या उनका सुन्न हो जाना।
- व्यक्ति को हाथ और पैरों में कमजोरी के कारण चलने में समस्या होना और अपना संतुलन खो देना
- गर्दन और कंधों पर अकड़न होना

गर्दन में दर्द के घरेलू उपाय

- सही ढंग से सोएं - अक्सर मुलायम ऊंचे गद्दे और तकिए पर हम सोना पसंद करते हैं। पर यह सर्वाइकल पेन का कारण हो सकता है इसलिए सख्त गद्दे का ही हमेशा प्रयोग करें। ऊंचे तकिया से दुश्मनी कर लें तो बेहतर है। अपना सिर जमीन के तल पर रखकर सोने की आदत डाल लें।
- गर्म सेख - दर्द कम करने के लिए गर्दन पर गर्म पदार्थ लेकर सिंकाई करें।
- खूब पानी पियें - हम यूँही नहीं कहते कि जल ही जीवन है। हमारे शरीर का अधिकतम वजन पानी की वजह से होता है क्योंकि शरीर में होने वाले अधिकांश कामो के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है।
- स्ट्रेस से बचें - आपको ये सुनकर थोडा अजीब लगेगा कि सर्वाइकल पेन की वजह स्ट्रेस यानी तनाव भी हो सकता है और यह कम से कम ६० फीसदी मामलों में देखा गया है

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें: therievtime@iirdshimla.org

सोशल मीडिया पर अब ग़लत व्यवहार पर रहें सतर्क

ऑनलाइन बदतमीजी पर लगने वाली धाराएं

IPC की धारा 507 : इस धारा के तहत कोई भी महिला अभद्र व्यवहार, अश्लील टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज करा सकती है। इसकी धारा में 'गुमनाम' को भी शामिल करने से ऑनलाइन इस तरह के अपराध करने वालों को भी पकड़ा जा सकता है। इस धारा के तहत मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वो आरोपी को पहचानकर पकड़े।

IPC की धारा 499 : भारतीय दंड संहिता की इस धारा में किसी के खिलाफ कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल करना, कोई तस्वीर दिखाना या किसी और तरह की कोई ऐसी हरकत करना जिससे किसी की प्रतिष्ठा खराब होती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

IPC की धारा 509 : महिला की प्रतिष्ठा के खिलाफ किसी भी तरह की गलत हरकत पर इस धारा के तहत मामला दर्ज कराया जा सकता है।

IPC की धारा 354 : दिल्ली में हुए शर्मनाक निर्भया मामले के बाद किसी भी तरह के महिला उत्पीड़न के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की इन धाराओं को शामिल किया गया है। इसमें ऑनलाइन भी किसी तरह के गलत व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

Mission RIEV and Sustainable Development Goals

Being apex international body, the United Nations keeps on setting agenda for human development periodically. After the Millennium Developmental Goals (MDGs), the introduction of Sustainable Development Goals (SDGs) outlines promotion of 17 aspects of overall well-being of the living being on earth and every country makes efforts to work for achievements of these goals through various means and measures.

On the other hand, Mission RIEV is also mandated to create ease of living and progress in life through facilitation support services. Wherever, people find difficulty in any of the aspects impacting life style or progress, whether individual or collective, the role of Mission RIEV starts. The activities, services and the support system envisaged under Mission RIEV are touching all 17 goals defined by United Nations as Sustainable Development Goals as outlined below:

1. Formation of Advisory Bodies- The Bodies being formed at Gram Panchayat, Block, District and State level have the mandate not only to provide guardianship and mentorship support to the Mission at appropriate level, but to plan, and execute activities pertaining to the common good close coordination with the communities. These activities include Emergency Services Disaster Risk Reduction (DRR), afforestation in denuded forest patches, water conservation and water usage, sanitation including overall cleanliness, maintaining water bodies, promotion of pesticide free natural farming, strengthening local governance institutions for promoting transparency and accountability, etc. These activities have direct relationship with the SDG NO.6 (Clean Water and Sanitation), SDG No. 13 (Climate Action), SDG No.14 (Life Below Water), SDG No.15 (Life on Land) and SDG No. 16 (Peace, Justice and Strong Institutions).

2. Institutionalized Service Division: Ten Service Divisions have been institutionalized under Mission RIEV to provide various felt need services and these Service Divisions have been trying to establish partnerships with the agencies owing the service products for operationalizing under Mission RIEV.

The multiple partnership initiatives with LIC India and SBI General Insurance Corporate agency, Bank of Baroda for getting 3500 POS machines etc., are adding values to the activities and service delivery of Mission RIEV and part of the SDG No. 17 (Partnership For the Goals). The Division Specific are briefed as below:

2.1. Education, Training & Counselling: As per the need assessment of the family especially in villages, the e-learning method of the Learning Management System is gaining wide popularity. Counselling and skill training are also being covered under this Division. The quality education is being provided even in the remote areas where teachers hardly serve with interest. These services significantly touch the SDG No. 4 (Quality Education).

2.2 Comprehensive Healthcare: Health Services are being provided at the door steps of the people right from medical test, video-conferencing with medical experts, supply of generic medicines at their door steps and follow up as well as referral appointment support. Apart from this, the preventive health education is also very important part of the Division Services. These services have direct relationship with SDG No. 3 (Good Health & Well Being).

2.3 Agri-Horti-Live Stock Services:
The services under this Division are primarily to promote and support natural practices and gradually zero downing the use of pesticides and other hazardous chemicals in agriculture, horticulture and livestock practice. The reduced pesticides and hazardous chemicals will prevent the aqua lives from depletion besides encouraging safe food production. These services have relationship with the SDG No. 1 (No Poverty), SDG No. 2 (Zero Hunger), SDG No.12 (Responsible Consumption and Production), SDG No.14 (Life Below Water).

2.4 Entrepreneurship and Business Development:
The services under this Division constitute identification of business potential in the aspirants, resource analysis, training needs assessment, orientation and training, bank linkages and providing business setup support besides mentorship for minimize one-year period for any start up. These services are directly related to the SDG No. 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG No. 9 (Industry Innovation & infrastructure) and SDG No. 5 (Gender Quality) women being encouraged under the services.

2.5 Banking and Financial Services:
The services under this Division include making due diligence, preparing loan cases including development of business proposals with financial analysis and getting the loans sanctioned followed by scheduled recoveries as well. These services have relationship with SDG No. 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) and SDG No.10 (Reduced Inequality) as the services are being provided to those weaker section people who keep on suffering because of the lengthy banking procedures and lose interest in furtherance of their objectives.

2.6 Land and Property Management:
There have been a number of land and property related pending concerns of the people in villages. The revenue authorities are not easily assessable and the procedures are also cumbersome with typical terminology beyond common person's understanding. Providing facilitation support services for fast and accurate resolution is mandate under the services of this Division and can have relationship with the SDG No.10 (Reduced Inequalities) and SDG No.16 (Peace Justice and Strong Institutions).

2.7. Rural Produce Marketing:
Under this Division, the farmers are facilitated with the quality production and getting reasonable and premium prices from the market as the farmer have to dispose-off their produce for loss many a times. These services have relationship with SDG No.10 (Reduce Inequalities), SDG No.11 (Sustainable Cities & Communities), SDG No.12 (Responsible Consumption & Production).

2.8: Utility, Licenses and Online Services:
In the present era of technology, majority of the services are available online for basic processing. Many utility services are also just on a call distance but requires basic set of skills. In order to venture into any business, there are some regulatory requirements which need to be fulfilled essentially. In order to save time and energy of the people, the facilitation support is given to the people at their door step. By doing this, people are finding themselves capable of doing the works they intend to, which otherwise used to be like long projects for them. Hence, this Division has relationship with the SDG No.10 (Reduce Inequalities).

2.9 Integrated Risk Management and Social Security: Apart from climate change and sustainability, special focus has been given on the Disaster Risk Reduction (DRR) including emergency services. When no one is there to listen a crying voice, Mission RIEV will not only listen but come forward to extend required support to the affected people. Capacity Building measures on DRR are being taken up by this Division in close coordination with the Advisory Boards. Apart from this, life, health & general insurances are also covered under the ambit of this Division and form the part of SDG. No. 11 (Sustainable cities & Communities).

Media Publication & Publicity:
This Division is auxiliary to all the other Service Divisions as it promotes the services being given by the other Service Divisions along with giving voice to the unheard and forms the part of the SDG. No. 10 (Reduced inequalities) and SDG No.11 (Sustainable Cities & Communities).

Hence, Mission RIEV is the only initiative which covers all the SDGs at the grass root level.

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

किसानों को कब तक ठगा जाऐगा

शिमला ग्रामीण में सब्जी मंडी के नाम पर मिला धोखा ही

अब तक हुए सरकारी नुकसान और पेड़ों के कटान पर खामोशी क्यों

हमारे देश का अन्नदाता वैसे तो किसानों को कहा जाता है परन्तु ये शब्द चुनावों के दौरान और नेताओं के संभाषणों में ही अधिक शोभा पाते हैं। उसके बाद तो पंचवर्षीय योजनाओं में देश के अन्नदाताओं के लिए लोक-लुभावनी चिकनी-चुपड़ी बातों का जायका ही परोसा जाता हैं। ज़िला शिमला की शिमला ग्रामीण विधानसभा अपने अस्तित्व में आने के बाद हिमाचल की सबसे हॉट सीट बन गई थी क्योंकि इस सीट पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपनी दावेदारी पेश की। उनके चुनाव लड़ने के बाद बहुत से ऐसे कार्यों को अंजाम तक लाने में भी सफलता मिली जो इससे पहले शिमला ग्रामीण में नहीं हुए थे। लेकिन बरसों से किसानों की एकमात्र मांग एक अदद सब्जी मंडी के निर्माण पर तत्कालीन सरकार ने देर-सवेर प्रयास तो किए परन्तु उसे अमलीजामा पहनाने से परहेज ही करते रहे। इस सब्जी मंडी से न केवल शिमला ग्रामीण बल्कि आसपास के एक बड़े दायरे में किसानों को सुविधा होती। सरकार के पास न केवल लोगों के स्थानीय निकायों के नुमायंदों ने बल्कि विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी समय-समय पर गुहार लगाई और सब्जी मंडी को निर्मित कर किसानों को राहत देने के लिए सरकार को जगाया ।

दरअसल वर्तमान में भी सब्जी मंडी या तो शिमला के हार्टकोर स्थल पर है जो कि न ही पर्याप्त स्थान रखती है और न ही शिमला के बीचोंबीच इसकी सार्थकता बन पा रही है । साथ ही बस स्टैंड या कार्टरोड़ से किसानों को अपने उत्पाद मजदूरी द्वारा ही सब्जी मंडी तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है । सरकार के पास कई प्रकार के प्रस्ताव समय-समय पर दिए गए तथा इसके लिए अनेक स्थलों का चयन भी किया गया । लालपानी के पास दाड़नी बगीचा हो या टूटु में भरयाल के पास की ज़मीन....मुआयना और रिपोर्टस जमा होती गई । अंततः टुटू में मजठाई पंचायत के अंतर्गत ज़मीन का चयन अंतिम प्रारुप के साथ सरकार ने स्वीकृत किया तथा समस्त औपचारिकताओं के साथ सब्जी मंडी का **शिलान्यास 29 अगस्त** 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया। शिमला ग्रामीण एवं आसपास के किसानों ने इसे एक एतिहासिक क़दम बताते हुए किसानों के लिए सुविधाजनक बताया। लेकिन जिस उत्साह से किसानों के लिए सब्जी मंडी का शिलान्यास हुआ, उसका निर्माण मात्र औपचारिकता बनता गया और किसानों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं । 2014 के बाद कई बार इस स्थल पर पूजन और भ्रमण करके सरकार की मंशा यह बताती है कि किसान घबराऐं नहीं....सरकार न तो किसानों का निराश होने देगी और न ही अपने लारेलप्पे छोड़ेगी । मुद्दा गर्म है और गर्म ही रखा जाऐगा ।

इसका दूसरा पहलु ये है कि तरतीब तरीक़े से तैयार की गई योजना पर सरकार का बजट भी स्वीकृत किया गया। कार्य भी आरम्भ किया गया। लेकिन सरकारी धन का श्रीगणेश करके आज स्थिति ये है कि वहां पेड़ों को काट कर अब सब्जी मंडी का निशान तक नहीं है। स्वीकृत बजट में से **18 लाख 72 हज़ार 216/ रुपये** खर्च कर दिए गए। उसके बाद किसान फिर से उसी प्रतीक्षा में जो निरंतर वर्षों से चली आ रही है।

मेरी एक सूचना के अधिकार में प्राप्त सूचना में ये आंकड़े सामने आए जिसमें सब कुछ तो है पर सब्जी मंडी नहीं अभी तक नहीं बनी है। इस सब्जी मंडी के निर्माण के लिए **297 लाख रुपये** का प्रावधान रखा गया है। जिसमें में स्वीकृत बजट का **18 लाख 72 हज़ार 216 रुपये** खर्चा किया जा चुका है। टुटू में जहां ये सब्जी मंडी बननी थी, वहां **364 पेड़ों** का कटान स्वीकृत किया गया था। जबकि काटे गए पेड़ों का वांछित आंकड़ा इस आरटीआई में नहीं दिया गया। यह सब्जी मंडी टुटू के बडहैरी, भरयाल, तहसील व ज़िला शिमला के अंतर्गत बनाई जानी थी। यहां पेड़ों की संख्या अधिका थी जिससे बहुत से पेड़ काट दिए गए। पेड़ तो काटे गए लेकिन सब्जी मंडी का काम न हो पाया। ये पेड़ हालांकि सरकार के दिशानिर्देश में स्पष्ट था कि 364 पेड़ों से अधिक न काटे जाऐं जिसमें 274 अलग प्रजाति के और 90 सैप्लिंग शामिल हो। वृक्ष कटान के बाद प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार यू-36 मंढोड़घाट में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 2.50 हे० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा और इतना ही नहीं, प्रतिपूर्ति पौधारोपण पत्र जारी होने की तारीख़ से एक से दो वर्ष के मध्य में पूर्ण किये जाने की अनिवार्यता है। इसके अलावा कार्यस्थल पर समीपवर्ती जंगल/वृक्षों को नुकसान न पहुंचे इसके लिए मजदूरों या स्टाफ को रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति को सुनिश्चित बनाया जाऐगा ।

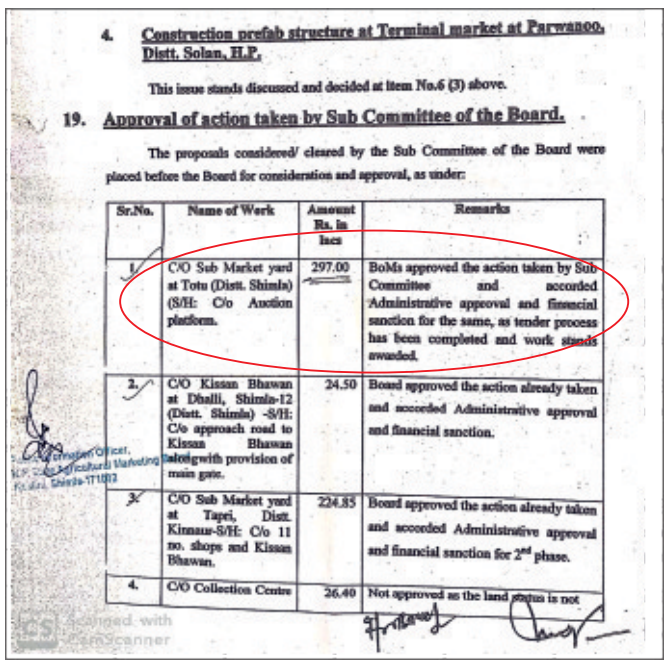

4. **Construction prefab structure at Terminal market at Parwanoo, Distt. Solan, H.P.**

This issue stands discussed and decided at Item No.6 (3) above.

19. **Approval of action taken by Sub Committee of the Board.**

The proposals considered/ cleared by the Sub Committee of the Board were placed before the Board for consideration and approval, as under:

Sr.No.	Name of Work	Amount Rs. in lacs	Remarks
1.	C/O Sub Market yard at Totu (Distt. Shimla) (S/H: C/o Auction platform.	297.00	BoMs approved the action taken by Sub Committee and accorded Administrative appeoval and financial sanction for the same, as tender process has been completed and work stands awarded.
2.	C/O Kissan Bhawan at Dhalli, Shimla-12 (Distt. Shimla) -S/H: C/o approach road to Kissan Bhawan alongwith provision of main gate.	24.50	Board approved the action already taken and accorded Administrative approval and financial sanction.
3.	C/O Sub Market yard at Tapri, Distt. Kinnaur-S/H: C/o 11 no. shops and Kissan Bhawan.	224.85	Board approved the action already taken and accorded Administrative appeoval and financial sanction for 2nd phase.
4.	C/O Collection Centre	26.40	Not approved as the land status is not

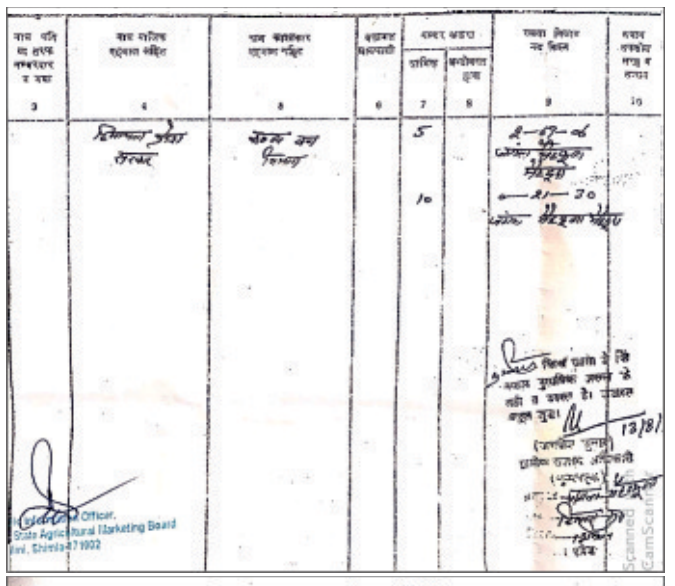

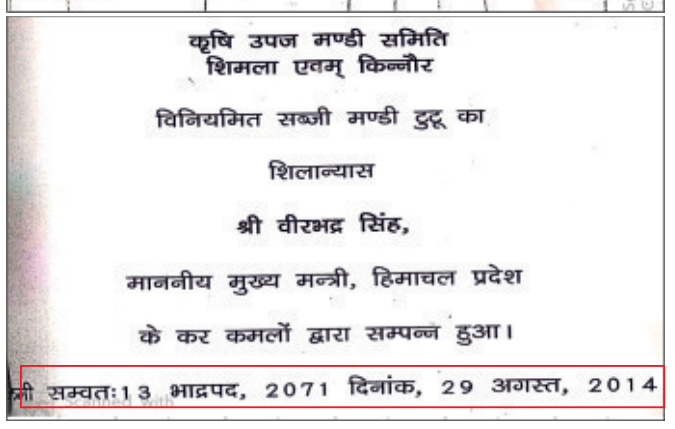

कृषि उपज मण्डी समिति
शिमला एवम् किन्नौर

विनियमित सब्जी मण्डी टुटू का

शिलान्यास

श्री वीरभद्र सिंह,

माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश

के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ।

सम्वत:13 भाद्रपद, 2071 दिनांक, 29 अगस्त, 2014

इस अदद सब्जी मंडी का निर्माण 4 माह में पूरा किया जाना था । बिड्स टेंटर नोटिस में यह स्पष्ट है कि 4 माह से अधिक का समय इसके निर्माण में नहीं लगेगा। जबकि इसकी DNIT राशि 1,56,71,919/ करोड़ रुपये थे। जबकि इसके लिए स्वीकृत राशि 2,24,65,500/ करोड़ रुपये हैं।

यहां प्रश्न यह है कि इस सब्जी मंडी के कार्य को धनराशि का प्रावधान हो जाने के बाद और उसे स्वीकृत राशि में से कुछ राशि का खर्च हो जाने के बाद भी वर्तमान में सब्जी मंडी का चयनित स्थल पर नामोनिशां तक नहीं हैं। कहां तो शीघ्रता इस सब्जी मंडी के निर्माण में दिखाई जानी चाहिए थी, कहां तो पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने में शीघ्रता का परिचय सरकार ने दिया और उसके बाद स्थिति जस की तस बनी हुई है । किसानों को वायदों का लॉलीपॉप थमा कर पिछली सरकार ने इसमें गंभीरता दिखाई होती तो शायद आज हमारे अन्नदाताओं यानि किसानों को अपनी सब्जियों के उत्पादों को लेकर यहां-वहां नहीं भटकना पड़ता। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसका विधिवत उद्घाटन किया तो उसके बाद वहां एक और भूमि पूजन भी करवाया गया जिसका बाजे-गाजे के साथ प्रचार किया गया। लेकिन किसानों की आशाओं पर पानी फेरने के अलावा कुछ नहीं हुआ । आज किसानों से जब इस विषय पर बात करते हैं तो उनको ठगा सा लगता है ।

सरकार को जनता की प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए राजनीति से उपर उठकर जनहित में कार्य करने की आवश्यकता है । टुटू क्षेत्र में अनेक पंचायतों के किसानों के लिए यह सब्जी मंडी एक आशा की किरण के रुप में निर्मित करने का योजना थी जिससे किसान अपनी सब्जियों और अन्य उत्पादों को समीप और उचित दामों पर उपलब्धता हेतु सुनिश्चित हुए थे । लेकिन सरकार ने इसमें भी किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया है। पिछली सरकार ने तो उद्घाटनों के दौर जारी रखें तथा पूजन आदि में ही समय बिता दिया जबकि वर्तमान सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है। यह मुद्दा अनेकों बार सरकार के समक्ष उठाया जा चुका है। अब यदि तू-तू, मैं-मैं की राजनीति से फुर्सत हो तो किसानों की इस चिरस्थिर मांग पर माननीय गंभीर हो जाऐं । साथ ही यह भी चिंतनीय विषय है कि कितने ही वृक्षों को काट कर ज़मींदोज़ किया जा चुका है और वृक्षारोपण के नाम पर वन विभाग का कोई माकूल ज़वाब नहीं आ रहा है । किसानों का अपराध ये है कि माननीयों को चुनने में ग़लती करते है या उन पर भरोसा करके वो स्वयं को ठगा सा महसूस करते रहेंगे । यह एक शोचनीय विषय है। सरकार को अतिशीघ्र जनभावनाओं का सम्मान करते हुए निर्धारित स्थल पर सब्जी मंडी का निर्माण का कार्य पूरा करना चाहिए ।

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

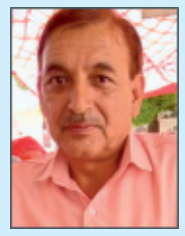

संबन्धित पंचायत टुटू मजठाई की प्रधान पूजा ठाकुर ने हमें बताया कि सब्जी मंडी के नाम पर हमारी पांच पंचायतों के साथ धोखा ही हुआ है। पिछली सरकार ने काम शुरु करवाया था और फिर वो बंद भी हो गया। ठेकेदार ने काम में दिलचस्पी नहीं ली और काम छोड़कर चला गया। उसके बाद वर्तमान सरकार का भी नकारात्मक रवैया देखकर समस्त किसान निराश है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस कार्य को शीघ्र ही आरंभ किया जाए ताकि किसानों को और अधिक परेशान नहीं होना पड़े।

इस बाबत जब संबन्धित पंचायत टुटू मजठाई से संपर्क किया गया तो उप-प्रधान रुप राम ने बताया कि सैंकड़ों बार उन्होंने पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार से डेलिगेशन के माध्यम से बात की गई और इस स्वीकृत कार्य को पूरा करने की गुहार लगाई गई है। लेकिन न तो हमारे प्रतिनिधियों ने सुनी और न ही मार्केटिंग बोर्ड इसमें दिलचस्पी ले रहा है । मौका पर जो कार्य किया भी गया था वो अब धूलधूसरित हो चुका है । किसानों में भारी निराशा है ।

पूर्व पंचायत प्रधान बल राज बताते हैं कि उनके कार्यकाल में ही इस सब्जी मंडी की नींव रखने और स्थान के चयन से लेकर अन्य समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया गया था। सरकार ने वोट की राजनीति को ध्यान में रखकर किसानों को छला है। ज़मीन भी राजस्व में हस्तांतरित की गई और एक समुचित बजट का प्रावधान भी सरकार से करवाया गया था। ठेकेदार ने थोड़ा-बहुत काम किया और उसके बाद कार्य बंद कर दिया गया। अब स्थिति ये है कि मौका पर किया गया कार्य भी ख़त्म हो चुका है साथ ही सारे पेड़ काटे जा चुके हैं। पूर्व सरकार तो इसके लिए दोशी है ही जबकि वर्तमान सरकार का भी इस ओर ध्यान न के बराबर है। सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वो स्वीकृत इस सब्जी मंडी को शीघ्र ही निर्माण कर किसानों की मांग को पूरा करें।

चम्याणा से पौधारोपण अभियान का आगाज

आईआईआरडी ने मिशन रीव के तहत बान और देवदार के 100 पौधे रोपे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आईआईआरडी की ओर से हाल ही मे मिशन रीव के तहत शिमला के चमयाणा में पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का आगाज आईआईआरडी के चेयरमैन प्रो. आरके गुप्ता द्वारा किया गया।

उन्होंने आईआरडी के प्रबंध निदेशक डा. एल.सी शर्मा के साथ मिलकर देवदार का पौधा रोपा। अभियान के पहले दिन चमयाणा में देवदार और बान के 100 पौधे रोपे गए।

इस मौके पर आईआईआरडी और मिशन रीव व फूलायर ग्रुप के सभी पदाधिकारियों व स्टाफ के अन्य सदस्यों ने पौधारोपण में अपना सहयोग दिया। पौधारोपण के इस अभियान की शुरूआत करते हुए आईआईआरडी के चेयरमैन प्रो. गुप्ता ने कहा कि आज विकास की अंधी दौड़ में हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जल, जंगल और जमीन को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में हर नागरिक का कर्त्वय है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा का जिम्मा उठाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक का कर्त्वय है कि वह नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इसके लिए आगे आए।

पौधारोपण के इस अभियान पर आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डाक्टर एलसी शर्मा ने कहा कि मिशन रीव के तहत प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में जलकल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। यही कारण है कि आईआईआरडी की ओर से हर वर्ष पौधारोपण अभियान चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि संस्था की ओर से केवल पौधे रोपे नहीं जाते बल्कि उनकी देखभाल का जिम्मा भी संभाला जाता है। डाक्टर शर्मा ने बताया कि कुछ सालों पहले चम्याणा में ही देवदार के पौधे रोपे गए थे। उनमें से 90 फीसदी पौधे सफल रहे हैं।

प्रबंध निदेशक ने कहा कि इस तरह का अभियान प्रत्येक पंचायत में पंचायत के सहयोग से मिशन रीव के तहत किया जाएगा और अन्य कार्यों में भी मिशन सहयोगी के तौर पर काम करने के लिए तत्पर है।

पौधारोपण के इस अभियान के दौरान निदेशक सुषमा शर्मा, फूलायर ग्रुप के सीईओ आनन्द नॉयर, मिशन रीव की सीईओ महरीन इकबाल समेत स्टाफ के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। चमयाणा गांव के स्थानीय निवासी टीटू जी भी उपस्थित रहे।

मुद्दा आधारित शिक्षा एवं जागरुकता कार्यक्रम

जल संरक्षण एवं स्वच्छ भारत अभियान में युवाओं की भूमिका

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुद्दा आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत नेहरु युवा केन्द्र संगठन हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से जल संरक्षण एवं स्वच्छ भारत अभियान पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पीटरहॉफ में किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं सचिव, युवा सेवा व खेल मंत्रालय भारत सरकार उपमा चौधरी ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। पीटरहॉफ के सभागार में 350 युवाओं ने हिमाचल भर से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।

नेहरु युवा केन्द्र संगठन द्वारा जल संरक्षण एवं स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए गए अभूतपूर्व कार्यों पर जानकारी दी गई। प्रभात कुमार ने समस्त आगंतुकों का स्वागत किया। मुख्यातिथि को शिमला पधारने और कार्यक्रम में भाग लेने पर सम्मान समारोह भी हुआ। साथ ही युवा मंडलों ने इस अभियान में किए बेहतरीन कार्यों पर प्रस्तुतिकरण किया। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से चयनित युवा मंडल के युवाओं ने जल संरक्षण पर अपनी गतिविधियों को विभिन्न माध्यमों से सामने रखा तथा इस बात पर पूरजोर तरीके से विचार प्रकट किए कि किस प्रकार हम अपने समाज और गांव को प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर युवा संगठन भड़ेच से सुरेन्द्र शर्मा, संदीप शर्मा, रामपुर से राज्य संभाषण प्रतियोगिता की विजेता नेहा वर्मा, यत्न युवा मंडल के जोगिन्द्र ने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर हिमाचल भर के 20 से अधिक

युवा मंडलों को पुरस्कृत भी किया गया। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता समाजसेवी हेम राज चौहान को इस क्षेत्र में सेवाओं के लिए उपमा चौधरी ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में नेहरु युवा केंन्द्र के निदेशक, उप-निदेशक, ज़िला युवा समन्वयक एवं कार्यक्रम प्रभारी प्रभात कुमार, सोलन ज़िला युवा समन्वयक ईरा प्रभात, अन्य ज़िलों के प्रभारी, सेवानिवृत डॉ० पीके आहलूवालिया, डॉ० एके भट्ट उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मुख्यातिथि उपमा चौधरी ने नेहरु युवा केन्द्र के कार्यों की सराहना की तथा युवाओं से सार्थक सुझाव मांगे। युवाओं ने अपने सुझाव भी साझा किए। प्रभात कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम युवाओं के लिए प्रेरणा भरा रहा तथा इस अभियान को गांव-गांव में युवा मंडलों के माध्यम से पहुंचाया जायेगा। मंच संचालन हेम राज चौहान ने किया। जबकि समस्त लोगों का धन्यवाद प्रस्ताव उप निदेशक सैमसन मसीह ने रखा।

नेहरु युवा केन्द्र संगठन, हि.प्र.
प्रभात कुमार

दिल्ली पहुंचा हिमाचल-जेएंडके सीमा विवाद का मामला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सीमा सरचू विवाद का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। लाहौल-स्पीति जिला परिषद अध्यक्ष रमेश रूअलबा ने सांसद रामस्वरूप को पत्र लिखकर शीघ्र सीमा विवाद हल करने का आग्रह किया है।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक रूअलबा ने कहा कि हिमाचल की सीमा सरचू से जम्मू कश्मीर के पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग करीब 17 किमी अंदर घुस आए हैं। वे जमीन पर अपना हक जताकर कारोबार चला रहे हैं। यही नहीं, जेएंडके पुलिस की अस्थायी चौकी भी हिमाचल सीमा के भीतर है।

दूसरी ओर जेएंडके के कारोबारी शिंकुला में 35 किलोमीटर अंदर घुसकर अपना कारोबार चला रहे हैं। रोहतांग सुरंग बनने के बाद सरचू पर्यटन की दृष्टि से अधिक विकसित होगा। ऐसे में विवाद और भी गहरा सकता है।

इस मसले को लेकर लाहौल-स्पीति के उपायुक्त केके सरोच ने वन अरण्यपाल कुल्लू को भी पत्र लिखकर सीमा विवाद देखने को कहा है। गौरतलब है कि हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक 10 अगस्त 2015 को सरचू में हुई थी। इसमें सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने मानचित्र के आधार पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर से जुड़े लोग हिमाचल में पर्यटन गतिविधियां चला रहे हैं। यहां तक कि जम्मू-कश्मीर की पुलिस भी हिमाचल की भूमि पर अस्थायी पुलिस चौकी लगा रही है। उधर, वन अरण्यपाल कुल्लू अनिल शर्मा ने कहा है कि उन्हें डीसी लाहौल-स्पीति की ओर से कोई पत्र नहीं मिला है।

10661 प्राथमिक पाठशालाओं में स्मार्टशाला से होगी गणित अंग्रेजी की पढ़ाई

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सम्पर्क स्मार्टशाला कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। यह कार्यक्रम गणित और अंग्रेजी विषयों में प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूलों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए और उनमें सीखने की क्षमता भी बढ़ाई जाए ताकि वे प्रतिस्पर्धी दुनिया के लिए स्वयं को तैयार कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और छात्रों में सीखने की क्षमता को बढ़ाना है ताकि स्कूली शिक्षा को सभी स्तरों पर समावेशी बनाया जा सके। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह स्मार्ट-किट निश्चित रूप से राज्य के लाखों छात्रों के लिए वरदान सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्पर्क स्मार्टशाला अंग्रेजी और गणित विषयों में सीखने में आने वाली बाधाओं को दूर करने व पाठशालाओं में लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी। इस कार्यक्रम से शिक्षकों को भी सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने सम्पर्क फाउंडेशन द्वारा इस परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपये का योगदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।

अब आयोग के अपने केंद्र से होंगी ऑनलाइन-ऑफलाइन परीक्षाएं

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1.75 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित आधुनिक ऑनलाइन कम्प्यूटर आधारित परीक्षा केन्द्र का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग समाज के उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि इस संस्था से राज्य की सेवा के लिए प्रतिभावान डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक और अन्य अधिकारी चयनित होंगे। उन्होंने कहा कि आज के दौर में लोगों को पारदर्शी, तत्पर और जवाबदेह व प्रशासन उपलब्ध करवाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आईटी के प्रभावी इस्तेमाल से न केवल कठिन कार्य को कम समय में पूरा किया जा सकता है बल्कि अभियार्थियों का विश्वास भी आयोग के प्रति बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि एक ही समय में आयोग लगभग 350 अभ्यार्थियों की ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा लेने में समर्थ होगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार आयोग का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके प्रभावी संचालन के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि आईटी के पूर्ण इस्तेमाल से अभ्यार्थियों को उनके दस्तावेजों को जमा करवाने के लिए शिमला नहीं आना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि अब अभ्यार्थियों को परीक्षा के एडमिट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अभ्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धर्मशाला में सुविधा केन्द्र स्थापित करने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

खाद्य सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार से दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन बाबत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने न्यायालय को बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 70 के मुताबिक खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए एपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन करना अति आवश्यक है। इस ट्रिब्यूनल के लिए जिला न्यायाधीश के स्तर का अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान बनाया गया है।

न्यायालय को बताया गया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रदेश में केवल कंडाघाट में एक स्थायी व दो अन्य चलती फिरती प्रयोगशालाएं हैं जो पर्याप्त नहीं हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश जारी किए थे कि वह और अधिक नियमित प्रयोगशालाएं स्थापित करने पर विचार करे क्योंकि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं की संख्या तीन लाख के लगभग है। मामले पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रमनियन व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ के समक्ष हुई।

हिमाचल में जुटेंगे देश भर के फुटबाल खिलाड़ी, चैंपियनशिप की तैयारियां शुरु

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश फुटबाल एसोसिएशन ने अंडर-14 और अंडर-17 नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऊना जिले में अंडर-17 नेशनल चैंपियनशिप नवंबर में होगी। अंडर-14 सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को लेकर मैदान के चयन की प्रक्रिया चल रही है। हमीरपुर और मंडी में से एक जगह अंडर-14 सब जूनियर चैंपियनशिप अगस्त अंत और सितंबर के बीच होगी। इसमें देश के नामी फुटबाल खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन के मैच कमिश्नर तपिश थापा ने अंडर-14 चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर हमीरपुर के अणु स्थित खेल मैदान का दौरा किया। उन्होंने जिला एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ खेल मैदान का निरीक्षण किया। मैदान में पाई गई कमियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए।

आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन ने प्रदेश और जिला फुटबाल एसोसिएशन (एआईएफएफ) से खिलाड़ियों के रहने-खाने समेत अन्य सुविधाओं को लेकर रिपोर्ट मांगी है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

कारगिल विजय दिवस – ऑपरेशन विजय को 20 साल पूरे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत ने 26 जुलाई 2019 को 20वां कारगिल विजय दिवस मनाया। इस कारगिल संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों को पूरे देश में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। सारा देश इस दिवस पर युद्ध में जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करता है। कारगिल युद्ध 03 मई 1999 से शुरू हुआ था। यह युद्ध लगभग ढाई महीने तक चला और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। कारगिल विजय दिवस के दिन देशभर में सैनिक, पुलिस और आम लोग भी देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। भारत की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि इस ऑपरेशन में सेना के करीब 527 जवान शहीद हुए और लगभग 1363 घायल हुए थे।

लोकसभा में पास हुआ मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक–2019

द रीव टाइम्स ब्यूरो

23 जुलाई 2019 को लोकसभा ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक - 2019 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में सड़क सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त नियम लागू किए गए हैं। विधेयक में ड्राइविंग के दौरान छोटी सी गलती पर भी भारी जुर्माना लगेगा। विधेयक के तहत अब बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, वाहन खतरनाक ढंग से चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, गाड़ी निर्धारित सीमा से तेज चलाना और अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यदि नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके माता-पिता और गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा। इस विधेयक के तहत गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

भारत में प्राइवेट 'क्रिप्टोकरेंसी' पर लगेगी रोक, मंत्रियों की समिति ने की सिफारिश

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हाल ही में अंतर मंत्रालयी समूह ने देश में क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित किसी भी तरह की गतिविधि हेतु जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। समूह ने इसके साथ ही एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा पेश करने का भी सुझाव दिया है। समूह ने कहा है कि इस डिजिटल मुद्रा का भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उचित तरीके से नियमन भी किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने 02 नवंबर 2017 को आर्थिक मामलों के सचिव की अगुवाई में एक अंतर मंत्रालयी समिति गठित की थी। इस समिति को आभासी मुद्रा से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन करने और इसके लिए कार्रवाई पर भी सुझाव देने का काम दिया गया। समिति के अन्य सदस्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव, सेबी के चेयरमैन और रिजर्व बैंक के डेप्युटी गवर्नर शामिल हैं।

चंद्रयान 2- भारत ने रचा इतिहास, इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया चंद्रयान-2

द रीव टाइम्स ब्यूरो

22 जुलाई 2019 को चन्द्रयान - 2 (Chandrayaan-2) मिशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरीकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। भारत इससे पहले 15 जुलाई को चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग करने वाला था, लेकिन क्रॉयोजेनिक इंजन में लीकेज के कारण इसे 22 जुलाई तक के लिए रोक दिया गया था। मिशन का सबसे पहला उद्देश्य चांद की सतह पर सुरक्षित उतरना और फिर सतह पर रोबोट रोवर संचालित करना है। इसका उद्देश्य चांद की सतह का नक्शा तैयार करना, खनिजों की मौजूदगी का पता लगाना, चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना और किसी न किसी रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाना है। चंद्रयान 1 की खोजों को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान-2 को भेजा गया है।

करतारपुर कॉरिडोर: प्रतिदिन 5,000 लोग बिना वीजा कर सकेंगे दर्शन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए रोजाना 5000 तीर्थयात्रियों को बिना वीजा आवागमन पर सहमति जताई है। यह गलियारा सिख श्रद्धालुओं हेतु गुरदासपुर जिला स्थित डेरा बाबा नानक साहिब से पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक जाना सुगम बनाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं, बल्कि ओसीआई कार्ड रखने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी करतारपुर कॉरिडोर सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने के भीतर फैसला सुनाने का आदेश दिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई 2019 को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को नौ महीने के अंदर फैसला सुनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 30 सितंबर को सेवानिवृत होने जा रहे विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल इस मामले की सुनवाई के समापन तक बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने सीबीआई के विशेष जज एसके यादव को नौ महीने के अंदर मामले पर फैसला सुनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई में सबूतों की रिकार्डिंग छह महीने में पूरी कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह बहुत जरूरी है कि सीबीआई जज एसके यादव मामले की सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाएं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश – सिनेमा हॉल में बाल यौन शोषण रोकने वाले वीडियो दिखाए जाए

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हाल ही में उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने देशभर के सिनेमा हॉल को बाल यौन शोषण और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम वाले वीडियो दिखाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय को उपयुक्त वीडियो की जांच सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट के अनुसार, टीवी चैनलों को भी ये वीडियो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के साथ दिखाने होंगे। उच्चतम न्यायालय बच्चों से दुष्कर्म और यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए खुद ही संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। न्यायालय ने मुद्दे पर सुझाव देने हेतु वरिष्ठ वकील वी. गिरी को न्यायमित्र नियुक्त किया था। कोर्ट ने इसके बाद सभी राज्यों एवं उच्च न्यायालयों से बच्चों से दुष्कर्म के मामलों के आंकड़े मंगवाए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 01 जनवरी से 30 जून 2019 तक देश में बच्चों से दुष्कर्म की कुल 24,212 घटनाएं हुईं हैं।

प्रीति पटेल ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी कैबिनेट में मंत्रियों की नियुक्ति करना शुरु कर दिये है। प्रीति पटेल ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बनीं। प्रीति पटेल कंजरवेटिव पार्टी नेतृत्व के लिए 'बैक बोरिस' अभियान की मुख्य सदस्य थीं। लोगों को पहले से ही संभावना थी कि उन्हें नई कैबिनेट में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। वे ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों के सभी प्रमुख कार्यक्रमों में अतिथि होती हैं। प्रीति पटेल का जन्म 29 मार्च 1972 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। वे 15 जुलाई 2014 को ब्रिटेन की राजकोष सचिव नियुक्त हुईं। वे साल 2010 में सांसद बनी थीं। वहीं साजिद जाविद मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाले थ। उन्होंने अब ब्रिटेन में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। साजिद जाविद साल 2018 में थेरेसा सरकार में ब्रिटेन के पहले नस्लीय अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले गृहमंत्री बने थे।

इंग्लैंड ने पहली बार जीता क्रिकेट विश्व कप का खिताब

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार विश्व चौम्पियन बन गई है। इंग्लैंड ने फाइनल में न्यूजीलैंड टीम को हराते हुए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 की ट्रॉफी पर कब्जा जमायज्ञं इंग्लैंड ने क्रिकेट विश्व कप के 44 वर्षों के इतिहास में पहली बार विश्व कप जीता है इंग्लैंड इससे पहले कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया था। इंग्लैंड को अपने घर पर विश्व कप जीतने का सुनहरा मौका मिला। इंग्लैंड के लॉर्ड्स में विश्व कप 2019 का फाइनल मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। न्यूजीलैंड की टीम ने मैच में पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट पर 241 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम ने भी निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट पर 241 रन ही बना सकी। इसके बाद सुपर ओवर का सहारा लिया गया।

अनुसुइया छत्तीसगढ़ व बिस्वा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में अनुसुइया उइके को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विश्व भूषण हरिचंदन को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उइके अर्जुन सिंह के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री रहते मध्य प्रदेश में मंत्री पद पर भी नियुक्त रही हैं। मध्य प्रदेश स्थित छिंदवाड़ा से ताल्लुक रखने वाली अनुसुइया उइके अपनी पिछली भूमिकाओं में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। बिस्वा हरिचंदन (84 वर्षीय) ओडिशा के चिल्का और भुवनेश्वर विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक रह चुके हैं।

पाक को एक और झटका, कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक

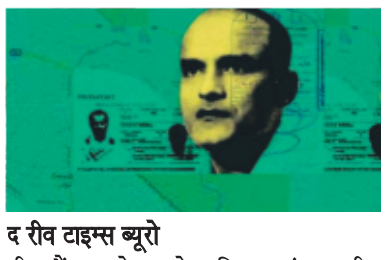

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नीदरलैंड्स के द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) ने भारत के कुलभूषण जाधव के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। आइसीजे ने अपने फैसले में कहा कि कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगेगी और कूलभूषण जाधव के केस पर फिर से नए सिरे से विचार होगा। आइसीजे ने पाकिस्तान को वियना समझौते का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई है और कहा है कि भारतीय राजनयिकों को जाधव से मिलने की इजाजत (काउंसिलर एक्सेस) दी जाए। अदालत ने 15–1 से भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद भारत का पक्ष रखने वाले वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अदालत से भारत को राहत मिली है।

विश्वभर में अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विश्वभर में अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई 2019 को मनाया गया है। रंगभेद के विरुद्ध लड़ाई लड़नेवाले विश्व नेता के रूप में नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नवम्बर 2009 में नेल्सन मंडेला दिवस मनाये जाने का प्रस्ताव पारित किया। मंडेला दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर कार्यों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें अच्छे उद्देश्यों हेतु एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रेरित करना है यह दिवस इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए उनके द्वारा किये गए संघर्ष और योगदान द्वारा विश्वभर में शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी मनाया जाता हैं।

बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

द रीव टाइम्स ब्यूरो

26 जुलाई 2019 को कर्नाटक में भाजपा विधायक दल के नेता बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह चौथी बार है जब उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बीएस येदियुरप्पा को राज्यपाल वजुभाई वाला ने राजभवन में एक समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

चंद्रशेखर आजाद की 113वीं जयंती

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत 23 जुलाई 2019 को चंद्र शेखर आजाद की 113वीं जयंती मनाई। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान की आहुति दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चंद्रशेखर आजाद बचपन में महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे। वे दिसंबर 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा थे। उस समय चंद्रशेखर आजाद की आयु महज 14 वर्ष थी।

चांद पर अमेरिकी मिशन अपोलो 11 के 50 साल पूरे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

गूगल ने अपोलो 11 मिशन के 50 साल पूरे होने पर डूडल बनाकर याद किया। नासा के इस मिशन में पहली बार चंद्रमा पर इंसान को उतरा गया था। अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये विश्वभर के लिए गर्व का दिन था। गूगल ने इसी मौके पर एक खास डूडल बनाया है। अपोलो का शुरुआती सफर 16 जुलाई 1969 को शुरू हुआ था और अब इसको पूरे 50 साल हो गए हैं। इस मिशन को नेडी स्पेस सेंटर के केप कनावेरल, फ्लोरिडा स्थित पैड से लॉन्च किया गया था। नासा ने नील आर्मस्ट्रांग के साथ बज एल्ड्रिन को अपोलो 11 मिशन पर भेजा था। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा था।

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन तीन बार रहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री

द रीव टाइम्स ब्यूरो

20 जुलाई 2019 को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शीला दीक्षित का निधन हो गया। वे 81 वर्ष की थी। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं। उनका अंतिम संस्कार 21 जुलाई 2019 को निगम बोध घाट पर हुआ। उन्हें लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। शीला दीक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में हुआ था।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

महीने भर में 3 जहाजों को जब्त कर चुका है ईरान

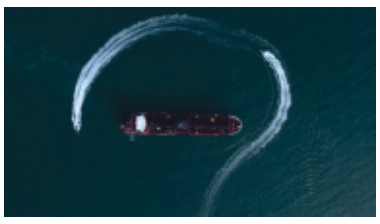

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ब्रिटिश अधिकारियों ने बाद में कहा कि गिरफ्तार किए गए क्रू सदस्यों में से कोई भी ब्रिटिश नागरिक नहीं है। IRA के बयान में कहा गया कि जहाज को बूशहर स्थानांतरित कर दिया गया और तस्करी कर लाए गए ईंधन को न्यायिक अधिकारियों के समन्वय में अधिकारियों को सौंप दिया गया। फार्स ने जब्ती की कार्रवाई करने वाले IRA के ब्रिगेडियर जनरल रमजाम जिराही के हवाले से कहा कि जहाज इस ईंधन को खाड़ी के अरब देशों को आपूर्ति करने के रास्ते में था। इस जहाज को जब्त किए जाने के साथ ही एक महीने से भी कम समय में ईरान खाड़ी जल में 3 जहाजों को जब्त कर चुका है।

अमेरिका ने अनुच्छेद 370 का बताया 'आंतरिक मामला', पाकिस्तान से एलओसी पर शांति बनाए रखने की अपील

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका ने कहा कि वह भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है।

अमेरिका ने कि वह भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है। साथ ही उसने सभी पक्षों से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोर्गन ओर्टागस ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा,"हम नियंत्रण रेखा पर सभी पक्षों से शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील करते हैं।" जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,"हम जम्मू कश्मीर की घटनाओं पर करीब से नजर रख रहे हैं।

हमने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक दर्जे में तब्दीली की भारत की घोषणा और राज्य को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में बांटने की योजना को संज्ञान में लिया है।"

उन्होंने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर में कार्रवाई को "पूरी तरह से आंतरिक मामला" बताया है। हालांकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर चिंता जताई। प्रवक्ता ने कहा, "हम हिरासत (जम्मू कश्मीर में) की खबरों पर चिंतित हैं और लोगों के अधिकारों के सम्मान तथा प्रभावित समुदायों से चर्चा की अपील करते हैं।"

धारा 370 हटने के बाद PoK में हड़कंप, फारुक हैदर ने कहा रोका नहीं गया तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर ऐसा होगा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री फारूक हैदर ने बयान दिया कि धारा 370 को खत्म करके भारत ने एक रणनीतिक चाल चली है।

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री फारूक हैदर ने बयान दिया कि धारा 370 को खत्म करके भारत ने एक रणनीतिक चाल चली है। फारुख हैदर ने मीडियो को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने जो कश्मीर में किया वह सीज फायकर लाइन (LoC) के उस तरह तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह खिसककर च्वज्ञ (पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) में भी आएगा, अगर आजाद कश्मीर में आया तो भारत और पाकिस्तान के बीच भी यह मुद्दा पैदा होगा।

इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस कदम के बाद कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय विवाद के पक्ष में पाकिस्तान अवैध कदमों का मुकाबला करने के लिए सभी संभावित विकल्पों का प्रयोग करेगा। पाकिस्तान ने कश्मीर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कश्मीर पर भारत सरकार के कदम को लेकर संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है।

चीन पर नकेल कसने के लिए एशिया में जल्द ही मिसाइलों की तैनाती करेगा अमेरिका

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका के नये रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने शनिवार को कहा कि उनका देश जल्द ही एशिया में मध्यम दूरी तक मार करने वाली नई मिसाइलें तैनात करना चाहता है।

अमेरिका के नये रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने शनिवार को कहा कि उनका देश जल्द ही एशिया में मध्यम दूरी तक मार करने वाली नई मिसाइलें तैनात करना चाहता है। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में चीन के उभरते दबदबे की काट करना है। यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका मध्यम दूरी तक मार करने वाले पारंपरिक हथियार एशिया में तैनात करने पर विचार कर रहा है क्योंकि अब वह्शिंगटन 'इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस' (INF) संधि से बंधा नहीं है, उन्होंने कहा, 'हां मैं ऐसा करना चाहूंगा।' आपको बता दें कि बीते काफी अरसे से चीन ने

एशिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए कई देशों में अपने बेस बना लिया है।

एस्पर ने कहा कि वह मिसाइलों की तैनाती जल्द से जल्द करना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अमेरिका इन हथियारों को कहां तैनात करना चाहता है? हालांकि माना जा रहा है कि मिसाइलों की तैनाती किसी ऐसी जगह पर होगी जहां से अमेरिका के लिए चीन पर नकेल कस पाना आसान होगा। एस्पर ने सिडनी जाते हुए अपनी फ्लाइट के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा, 'मैं चाहूंगा कि यह सब कुछ महीनों में हो जाए लेकिन इन चीजों में आपकी उम्मीद से अधिक समय लगता है।' आपको बता दें कि अमेरिका शुक्रवार को INF संधि से हट गया था। अमेरिका ने रूस पर इसका वर्षों से उल्लंघन करना का आरोप लगाया।

क्या है इस संधि में

इस संधि पर 1987 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव के बीच ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें वॉशिंगटन और मास्को ने पारंपरिक और परमाणु मध्यम दूरी की मिसाइलों (500 से 5000 किलोमीटर) का इस्तेमाल सीमित करने पर सहमत हुए थे। एस्पर ने कहा कि चीन को अमेरिकी की योजना से हैरानी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'इससे हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इस बारे में कुछ समय से बात कर रहे थे।'

पानी के जहाज में छिपकर भारत पहुंचे थे मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति, वापस भेजते ही हुए गिरफ्तार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय अधिकारियों द्वारा गफूर को वापस उनके देश भेजे जाने के बाद शनिवार को मालदीव पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

मालवाहक जहाज से तमिलनाडु पहुंचकर भारत में राजनीतिक शरण की मांग करने वाले मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों द्वारा गफूर को वापस उनके देश भेजे जाने के बाद शनिवार को मालदीव पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गफूर गुरुवार को समुद्र के रास्ते एक मालवाहक जहाज से तमिलनाडु पहुंचे थे लेकिन उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया गया था। कई केंद्रीय एजेंसियों ने जहाज पर ही उनसे पूछताछ की थी।

क्रू के पीछे छिपे हुए थे अदीब

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदीब सिंगापुर के झंडे वाली बोट पर क्रू के सदस्यों के पीछे छिपे हुए थे। तूतीकोरिन में एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति को अधिकारियों ने उतरने नहीं दिया था क्योंकि उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। उन्हें वापस उनके देश भेज दिया गया था। मालदीव पुलिस ने शनिवार को कहा, 'हम इस बात की पुष्टि करना चाहेंगे कि एच सामरा के अहमद अदीब अब्दुल गफूर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें हमारे संरक्षण में माले लाया जा रहा है।'

वकील ने कहा, खतरे में है अदीब की जान

गफूर का प्रतिनिधित्व कर रही एक कंपनी के ब्रिटिश वकील टोबी कैडमैन ने कहा, 'हमें इस बात की गहरी चिंता है कि उन्हें मालदीव को लौटाया जा सकता है जहां उनकी जान जोखिम में है। उन्होंने शरण के लिए अनुरोध किया है और उसे मान लिया जाना चाहिए।' अदीब की कानूनी टीम के अनुसार, उनकी तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन से अनबन हो गई थी और यामीन की हत्या के लिए बम धमाके की साजिश को लेकर उनकी जांच की गई।

अमेरिका: टेक्सास के मॉल में दिन-दहाड़े गोलीबारी, 20 की मौत, कई घायल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

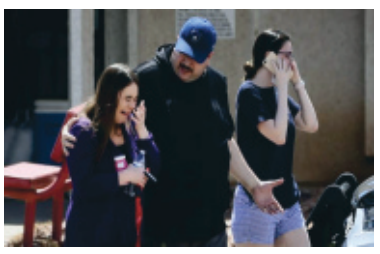

संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत के अल पासो में स्थित एक शॉपिंग मॉल में शनिवार को हुई गोलीबारी में 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत के अल पासो में स्थित एक शॉपिंग मॉल में हुई गोलीबारी में 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है। एक अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस घटना में कई

सीएनएन ने अल पासो के मेयर के चीफ ऑफ स्टाफ ओलिविया जीपेडा के हवाले से बताया कि मॉल में गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई। घटना के बारे में बात करते हुए टेक्सास के गवर्नर ने बताया कि यह राज्य के इतिहास के सबसे घातक दिनों में से एक था। फोन के कैमरों से बनाए गए वीडियो में स्टोर के पार्किंग वाले इलाके में कई शव बिखरे नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में भयभीत खरीददार जान बचा कर स्टोर से बाहर की ओर भागते दिख रहे हैं।

गोलीबारी की इस घटना के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, 'टेक्सास के अल पासो में भयानक गोलीबारी हुई है। बेहद बुरी खबर है और बहुत से लोग मारे गए हैं।' उन्होंने बताया कि कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। ट्रंप ने कहा, घटना के संबंध में गवर्नर से बात हुई है। फेडरल गवर्नमेंट का पूरा समर्थन रहेगा। भगवान आप सभी के साथ है।'

रेंडशिप डे पर दो भारतीय दोस्तों को UAE में मिला बड़ा तोहफा, एक झटके में हो गए मालामाल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में दो भारतीय दोस्तों ने एक बड़ी लॉटरी जीती है। इसमें से एक दोस्त पूर्व में दुबई का निवासी रहा है और दूसरा वर्तमान में अबू धाबी में है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विलास रिक्काला व रवि मासिपेद्दी भारत के तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले के रहने वाले हैं। वे काफी लंबे समय से टिकट खरीद रहे थे और आखिरकार 29 जुलाई को खरीदा गया टिकट उनके लिए भाग्यशाली साबित हुआ। बिग टिकट अबू धाबी लॉटरी की पुरस्कार राशि 1.5 करोड़ दिरहम (40 लाख डॉलर) है।

रिक्काला भारत लौट आए हैं। वह इस अनपेक्षित लाटरी से चकित और मगर खुश हैं।रिक्काला ने खलीज टाइम्स से फोन पर कहा, मेरे पास इसे जाहिर करने के लिए शब्द नहीं हैं। यह एक सपने की तरह है। मैंने दुबई की कंपनी में 4-5 साल काम किया और फिर चला आया और अब मेरे पास यह जैकपॉट है। अबू धाबी में काम करने वाले मासिपेद्दी ने कहा, मैं बता नहीं सकता कि कितने साल से इसे खरीद रहे हैं। आखिरकार हम जीते हैं। हमने 50 फीसदी राशि टिकट खरीदने में लगाई है। विजेताओं की सूची में पांच अन्य भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। बिग टिकट अबू धाबी में नकद पुरस्कार और लक्जरी कारों के लिए सबसे बड़ा मासिक लॉटरी ड्रा है।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

द रीव टाइम्स संस्थापक: डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित
प्रधान सम्पादक: डा. एल.सी. शर्मा
फोन न. 0177 2640761, मेल: editor@themissionriev.com
Title Code : HPBIL00313
RNI Reference No. 1328500

कनाडा के शहर फ्रेडरिक्टन में गोलीबारी में 4 की मौत, संदिग्ध को पुलिस ने दबोचा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित शहर फ्रेडेरिक्टन में गोलीबारी की घटना में कई लोगों के हताहत होने की बात सामने आ रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना में अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को पकड़ लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, संदिग्ध को पुलिस ने दबोच लिया। हालांकि अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है।

पुलिस ने ब्रुकसाइड ड्राइव में मेन स्ट्रीट और रिंग रोड के बीच हुई इस घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी थी। साथ ही पुलिस ने लोगों को अपने घरों को लॉक करके अंदर ही रहने की हिदायत भी दी थी। साथ ही अधिकारियों ने लोगों से ब्रुकसाइड ड्राइव के इलाके में लोगों से एहतियात से काम लेने के निर्देश दिए थे।

एक स्थानीय व्यक्ति ने दावा किया कि गोली की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। उसने दावा किया कि अगले एक से डेढ़ घंटे के बीच कम से कम डेढ़ दर्जन फायर और किए गए। आपको बता दें कि फ्रेडरिक्टन एक छोटा-सा शहर है जहां लगभग 60,000 लोग रहते हैं। यह न्यू ब्रन्सविक प्रांत की राजधानी भी है।

कश्मीर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बीच पाक पीएम इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप से लगाई गुहार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

खास बातें

- पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कश्मीर को लेकर दिया बयान
- पाक पीएम ने कश्मीर मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप से की मध्यस्थता की अपील
- जम्मू-कश्मीर में बिगड़े हालात का दिया हवाला

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। अब ऐसा करने का समय आ गया है क्योंकि वहां हालात खराब हो रहे हैं और नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना नए आक्रामक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्रीय संकट को हवा देने वाले कदम हैं। पाक पीएम ने भारत के साथ अचानक बढ़े तनाव के मद्देनजर रविवार को देश के शीर्ष नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए एनएससी की बैठक भी बुलाई।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

- भूटान और जिस देश के मध्य व्यापार को सहज बनाने के उद्देश्य से भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी में आवागमन के लिये एक जलमार्ग खोला है - बांग्लादेश
- हाल ही में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, जिस देश में जलवायु परिवर्तन केवल पारिस्थितिकी तंत्र के लिये ही खतरा नहीं है, बल्कि इससे पुरातात्विक इमारतों एवं स्थलों को भी क्षति पहुँच रही है - ग्रीनलैंड
- हाल ही में जिस टेनिस खिलाड़ी ने रॉजर फेडरर को हराकर लगातार दूसरा विंबलडन खिताब जीत लिया है - नोवाक जोकोविच
- वह देश जो आईसीसी विश्व कप 2023 के 13वें संस्करण की मेजबानी करेगा - भारत
- अफगानिस्तान के जिस लेग स्पिनर को तीनों ही फॉर्मेट में टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है - राशिद खान
- वह भारतीय मुक्केबाज जिसने अमेरिका के माइक स्नाइडर को हराकर पेशेवर मुक्केबाजी में लगातार 11वीं जीत दर्ज की है - विजेंदर सिंह
- बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा को जिस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है - हिमाचल प्रदेश
- इंग्लैंड ने जिस देश को हराते हुए पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता - न्यूजीलैंड
- हाल ही में जिसे विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है - अंशुला कांत
- तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली की पहली खेप तुर्की पहुँचने पर जिस देश द्वारा प्रतिबंध लगाने की आशंका जताई है - अमेरिका
- हाल ही में वह देश जिसने अपना एयरस्पेस भारत के लिए खोल दिया है - पाकिस्तान
- वह देश जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्वकप 2020 की मेजबानी करेगा - भारत
- हाल ही में चीन ने जिस देश से तिब्बती गुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देने का आग्रह किया - भारत
- पाकिस्तान ने जिस पवित्र गुरुद्वारे में भारतीय तीर्थयात्रियों को वर्ष भर के लिये वीजा मुक्त प्रवेश देने पर सहमति व्यक्त की है - करतारपुर साहिब
- हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा की गई ऑर्किड की पहली व्यापक जनगणना के अनुसार, जिस देश में ऑर्किड प्रजाति या वर्गिकी की कुल संख्या 1,256 पाई गई - भारत
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में केंद्र सरकार, पंजाब और जिस राज्य को सतलुज-यमुना को जोड़ने वाली नहर से जुड़े मुद्दे को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से हल करने को कहा है- हरियाणा
- हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक वैकल्पिक विषय के तौर पर मैथिली को शामिल किये जाने की घोषणा की है - दिल्ली सरकार
- वर्ष 2019 में चन्द्र ग्रहण के दिन आने वाली गुरु पूर्णिमा का संयोग जितने वर्षों बाद बना - 149
- ICC द्वारा हाल ही में जारी विश्व कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट की घोषणा की, इसमें रोहित शर्मा के अतिरिक्त जिस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है - जसप्रीत बुमराह
- इन्हें हाल ही में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया - अनुसुइया उइके
- इन्हें हाल ही में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है - बिस्वा भूषण
- वह सोशल मीडिया वेबसाइट जिस पर अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग ने 5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है - फेसबुक
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने इस शिक्षण संस्थान के साथ मिलकर उत्तर भारत में 'स्किन-बैंक' स्थापित किये जाने की घोषणा की है - आईआईटी-दिल्ली
- वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या कम हो रही है लेकिन मोटापे से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ रही है - एफएओ
- इन्हें हाल ही में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है - न्यायमूर्ति ए के सीकरी
- एनजीटी ने गंभीर और अति गंभीर प्रदूषित इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां बंद कराने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इतने माह का वक्त दिया है - तीन
- संगीत नाटक अकादमी द्वारा इन्हें 2018 के संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप (अकादमी रत्न) के लिए चुना है - सोनल मानसिंह
- वह राज्य जिसके मंत्रिमंडल ने शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किये जाने की घोषणा की है - महाराष्ट्र
- केंद्र सरकार के बाद जिस राज्य ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है - पश्चिम बंगाल
- L&T के ग्रुप चेयरमैन जिन्हें हाल ही में आईटी कंपनी माइंडट्री का गैर-कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है - ए.एम. नाइक
- हाल ही में जिस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय और जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये राज्यसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया - आंध्र प्रदेश
- जिस शहर में हाल ही में संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप (अकादमी रत्न) एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई - नई दिल्ली
- केंद्र सरकार सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में जिस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बना रही है - रोटावायरस
- वह राज्य जो देश में 'जल नीति' पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है - मेघालय
- वह देश जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 76वां देश बना है - पलाऊ
- जिस राज्य के विधि आयोग ने मॉब लिंचिंग की बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर ऐसे मामलों में शामिल आरोपियों को उम्रकैद की सजा देने की सिफारिश की है - उत्तर प्रदेश
- प्रत्येक साल 18 जुलाई को जिस दिवस को मनाया जाता है - नेल्सन मंडेला दिवस
- हाल ही में जिस देश ने लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में वैश्विक स्तर पर पहली बार सोयाबीन के सतत् उत्पादन के लिये ग्रीन बॉन्ड प्रस्तुत किया - ब्राजील
- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने हाल ही में जिस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है - सचिन तेंदुलकर
- आईसीसी ने सरकारी दखलअंदाजी को लेकर जिस क्रिकेट टीम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है - जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम
- वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में शहीद होने तथा अक्षम हो जाने वाले सैनिकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है - महाराष्ट्र सरकार
- हिमा दास ने महिलाओं की जितने मीटर की दौड़ में 15 दिन के अंदर ही चौथा स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है - 200 मीटर
- डब्लूएचओ द्वारा हाल ही में जिस देश में दो मिलियन लोगों के घातक इबोला वायरस से ग्रसित होने पर अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है - कांगो
- हाल ही में फीफा द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबाल टीम को जो स्थान प्राप्त हुआ है - 103
- हाल ही में जिस भारतीय खिलाड़ी ने सेना में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल ज्वाइन किया और वे कश्मीर में 15 दिन की ट्रेनिंग आरंभ कर रहे हैं - एम एस धोनी
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गये निर्देश के अनुसार देश के किसी भी जिले में जितने केस POCSO एक्ट के तहत दर्ज होने पर वहां एक स्पेशल कोर्ट बनाया जायेगा - 100
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस नाम से रक्षा उत्पादन विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रभावी निगरानी में सहायक विभाग का डैशबोर्ड लांच किया है - www.ddpdashboard.gov.in
- प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाये जाने वाले कारगिल विजय दिवस की वर्ष 2019 में जो वर्षगांठ मनाई जा रही है - 20वीं
- हाल ही में जारी एटीपी टेनिस रैंकिंग में जिस महिला खिलाड़ी को पहला स्थान मिला है - एश्ले बार्टी
- भारतीय वनस्पति शोधकर्तृताओं ने जिस राज्य में एक रक्त स्रावित वृक्ष की प्रजाति ड्रैकैना कैम्बोडियाना की खोज की है - असम
- हाल ही में नई दिल्ली में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है - 52
- हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग के न्यू इकोनॉमी ग्लोबल सर्वे के अनुसार, वर्ष 2035 तक भारत और जिस देश विश्व के तकनीकी नवाचार केंद्र के रूप में अमेरिका से आगे निकल जायेगा - चीन
- अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जिस महानिदेशक का 72 साल की आयु में निधन हो गया - युकिया अमानो
- सांसद व पूर्व फुटबॉलर प्रसून बनर्जी और राष्ट्रीय हाकी टीम के पूर्व सदस्य केशव दत्त को साल 2019 में जिस पुरस्कार से नवाजा जाएगा - मोहन बगान रत्न
- टीम इंडिया की जर्सी पर ओप्पो मोबाइल के बाद अब जिस कंपनी ने नाम प्रदर्शित करने के अधिकार खरीदे हैं - बायजू
- ट्राई ने अक्टूबर 2016 में रिलायंस जियो को इंटर-कनेक्टिविटी सुविधा नहीं देने के कारण दंड स्वरूप एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया पर जितना जुर्माना लगाया है - 3050 करोड़ रुपये
- वह शिक्षण संस्थान जिसने वृद्ध लोगों के लिए CARE4U नामक एप्प लांच किया है - आईआईटी खड़गपुर
- भारत में प्रत्येक वर्ष जिस दिन आयकर दिवस मनाया जाता है - 24 जुलाई
- जिसे देश का नया गृह सचिव बनाया गया है - अजय कुमार भल्ला
- नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने 34,422 करोड़ रुपए की जिस योजना को शुरू करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किया हैं - पीएम-कुसुम योजना
- ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बॉरिस जॉनसन ने अपनी कैबिनेट में जिसे गृह मंत्री का पद दिया है - प्रीति पटेल
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शहर में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति में म्यूजियम बनाने की घोषणा की है - दिल्ली
- हाल ही में मध्य प्रदेश विधान सभा में ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर जितने फीसदी करने का विधेयक पास हो गया - 27 फीसदी
- भारत द्वारा चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण के बाद जिस देश ने भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर काम करने की इच्छा व्यक्त की है - चीन
- थेरेसा मे द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद हाल ही में जिसे यूनाइटेड किंगडम का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है- बोरिस जॉनसन
- जिस दिन को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है - 23 जुलाई
- भारत के जिस संस्थान के छात्रों ने कृषि संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए 'स्मार्ट-एग्रीकॉप्टर' बनाया है - आईआईटी मद्रास
- केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत जितने और हवाई मार्गों कों जोड़ा गया है - 8
- हाल ही में जिस देश ने कार्बन टैक्स की शुरुआत की है - दक्षिण अफ्रीका
- विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नामक गैर-सरकारी संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के जिस शहर के वातावरण में पिछले एक साल के दौरान ओजोन के प्रदूषक कणों की मात्रा में लगभग डेढ़ गुना वृद्धि हुई है - दिल्ली
- हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में 922 अंकों के साथ जिस भारतीय खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर काबिज है - विराट कोहली
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि का अनुमान 2019 के लिए 7.3 प्रतिशत घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है - 7 प्रतिशत
- हाल ही में जिस सरकारी विभाग ने वेंडरों द्वारा मनमानी कीमत वसूल किये जाने की शिकायत पर 'नो बिल, नो पेमेंट' अभियान आरंभ किया है - भारतीय रेल
- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस रियल एस्टेट कंपनी का रेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल करने का आदेश दिया है - आम्रपाली ग्रुप

हिमाचल सामान्य ज्ञान

- प्रदेश सरकार निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहां पर स्थापित किया जा रही है - शिमला
- हिमाचल प्रदेश विवि के 50वां स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विवि का बजट 115 से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया - 130 करोड़
- विवि की स्थापना कब की गई थी - 22 जुलाई 1970
- हिमाचल प्रदेश विज्ञान और पर्यावरण परिषद और पर्यावरण विभाग, भारत सरकार और सर्व शिक्षा अभियान के तहत 10–17 वर्ष के बच्चों को उनकी रचनात्मक तथा नवीनता को प्रदर्शित करने के लिए लिए 27वीं बाल विज्ञान कांग्रेस कर आयोजन - शिमला
- प्रदेश में राजनीति के पुरोधा और पूर्व में शिक्षामंत्री रहे किस व्यक्ति का हाल ही में निधिन हो गया - पंडित शिव कुमार उपमन्यू
- हिमाचल की किन दो विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं - धर्मशाला और पच्छाद
- हाल ही हिमाचल के नए राज्यपाल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है - कलराज मिश्र
- हिमाचल प्रदेश के किस खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय अलट्रा मैराथन धावक के रूप में ख्याति प्राप्त है - सुनील कुमार, जो सिरमौर से
- हिमाचल भूतपूर्व सैनिक निगम हमीरपुर का अध्यक्ष किसे बनाया गया है - खुशाल सिंह
- फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक हिमाचल में वनों की अधीन कितना क्षेत्रफल बड़ा है - 12 वर्गकिलोमीटर
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं के लिए प्रदेश के कितने जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा - 3, शिमला, सिरमौर, मंडी
- थाईलैंड ओपन बाक्सिंग में गोल्ड जीता - आशीष शर्मा, मंडी सुंदरनगर से
- हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, जिसे हाल ही में भंग कर दिया गया की स्थानपना कब की गई थी - 1986 में
- नंवबर 2019 में धर्मशाला में प्रस्तावित इनवेस्टर मीट में कितना निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य निधार्रित किया गया - 85,000 करोड़
- मिंजर मेले के दौरान मिंजर किस नदी में बहाई जाती है - रावी
- मिंजर मेला जुलाई के कौन से रविवार से शुरू होता है - अंतिम रविवार से
- मिंजर मेला किस राजा की कांगड़ा पर जीत का प्रतीक भी माना जाता है - साहील वर्मन
- प्रदेश सरकार की ओर से रोपे गए पौधों की निगरानी के लिए कौन सी एप लॉच की है - प्लांटेशन मॉनीटरिंग सिस्टम
- पापा अभियान क्या है- प्रदेश सरकार की ओर से प्रदूषण को रोकने के लिए चलाया गया अभियान- पॉल्यूशन अबेटिंग अभियान
- भारती की महिला हैंडबॉल टीम में कितनी हिमाचली खिलाड़ियों का चयन हुआ - 4 - प्रियंका ठाकुर, शालिनी ठाकुर, दीप शिखा
- कांगड़ा की कितनी पंचायतों के इंडस्ट्रियल कोरीडोर में शामिल किया जा रहा है - 10
- बबीएमबी किस जिले में पावर प्रोजेक्ट लगाएगा - मंडी जिले में बग्गी में
- बागवानी प्रोजेक्ट दो मे कितने जिलों को शामिल किया गया है - 4 - कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर

सामार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को 6000 रुपए की मदद मिलती है। सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को छोड़कर हर गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला को यह मदद मिलती है। इस लेख में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? इसका लाभ पाने के लिए नियम व शर्तें क्या हैं। आवेदन प्रक्रिया क्या है? और यह भी कि कौन सी स्थितियों में इसका फायदा नहीं मिल सकता।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के निर्देशों के तहत-गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और जच्चा-बच्चा (मां व संतान) को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है। 01 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लांच किया था।

इसके माध्यम से हर गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिला को 6000 रुपए तक आर्थिक मदद दी जाती है। देश के सभी जिलों में इसे लागू किया गया है। Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana का संचालन आंगनवाड़ी केंद्रों या स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के माध्यम से होता है। इस योजना का लाभ सभी आय वर्ग (All Income Class) की गर्भवती महिलाओं को मिल सकता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उददेश्य?

कमजोर आय वर्ग की महिलाएं आर्थिक तंगी के कारण गर्भावस्था के अंतिम दिनों के दौरान भी रोजगार से संबंधित कामों में लगी रहती हैं। बच्चे के जन्म के बाद भी पर्याप्त आराम के पहले ही काम करना शुरू कर देती हैं, जबकि उनका शरीर इसके लिए तैयार नहीं होता। इससे दोहरा नुकसान होता है।

पहला, महिला खुद के स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान और समय नहीं दे पाती, जिससे वे कमजोरी, रक्ताल्पता, जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो जाती हैं। इसका असर उसकी होने वाली संतान पर भी पड़ता है।

दूसरा, शिशु के जन्म के बाद शुरुआती छह महीनों तक उसे मां के दूध की लगातार जरूरत होती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और बच्चे को बाद में भी पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता।

इन दोनों समस्याओं के समाधान के रूप में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की है। इसके तहत कमजोर आयवर्ग की महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि उन्हें मजदूरी में नुकसान के एक हिस्से की भरपाई हो सके। इससे एक तरफ महिला को पर्याप्त विश्राम लेने में सहूलियत होगी और दूसरी तरफ महिला व बच्चे को पोषण के लिए भी मदद होगी।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभ किसे?

कुछ निश्चित श्रेणियों को छोड़कर (नीचे उनका जिक्र किया गया है), सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मानी गई हैं।

योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा भी (योजना की शर्तों के तहत होने पर) लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

किसे नहीं मिल सकता लाभ:

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जिन श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं माना गया हैं, वे इस प्रकार हैं-

सरकारी कर्मचारी केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में कार्यरत महिलाएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ नहीं ले सकतीं, क्योंकि, उनकी सेवाशर्तों में वेतन सहित मातृत्व अवकाश जैसे लाभ पहले से ही जुड़े होते हैं।

किसी अन्य कानून से लाभ पा रही प्राइवेट कर्मचारी जो महिलाएं किसी प्राइवेट संस्थान में कार्यरत है, लेकिन वहां लागू किसी अन्य कानून के तहत मातृत्व लाभ की सुविधा प्राप्त कर रही हैं, वे भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मदद प्राप्त नहीं कर सकतीं।

पहले सभी किस्तें पा चुकी महिला आपने इसके पहले कभी अन्य संतान के जन्म के दौरान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले सभी किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं, तो भी आप इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारी नहीं हैं।

तीन किस्तों में बंटकर मिलती है मदद राशि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को सरकार से मिलने वाली मदद तीन किस्तों में मिलेगी।

कब मिलेगी किस्त की राशि

पहली किस्त– आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भधारण का पंजीकरण कराने पर (गर्भ के 150 दिनों के अंदर) 1,000 रुपये

दूसरी किस्त– गर्भधारण के छह माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर (गर्भ के 180 दिनों के अंदर) 2,000 रुपये

तीसरी किस्त–बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने तथा बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हैपेटाइटिस बी आदि टीकों का प्रथम चक्र पूरा होने पर 2,000 रुपये

शेष 1000 रुपए का भुगतान: दरअसल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत तीन किस्तों में 5000 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन लाभार्थी महिला के किसी संस्था (सरकारी या अनुमोदित अस्पताल) में प्रसव कराने पर जननी सुरक्षा योजना के तहत 1000 रुपए की मदद अतिरिक्त रूप से मिलती है। इस प्रकार प्रत्येक महिला को कुल 6000 रुपए तक मातृत्व लाभ दिया जाता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फायदा पहली बार मां बनने वाली महिला या पहले जीवित बच्चे के मामले में ही मिलता है। योजना के लाभ के लिए आवेदन में लाभार्थी महिला व उसके पति को भी इस बात की घोषणा भी करनी होती है कि यदि प्रसव सफल रहा तो यह उनका पहला जीवित बच्चा होगा।

गर्भपात, मृत जन्म, शिशु मृत्यु के मामले में नियम

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फायदा पहली बार मां बनने वाली महिला या पहले जीवित बच्चे के मामले में ही मिलता है। वास्तव में यह योजना किसी एक महिला को एक बार ही मदद की सभी किस्तें पाने का हक देती है। गर्भपात, मृत जन्म या शिशु मृत्यु की स्थिति में निम्नलिखित तरीकों से लागू होंगें।

गर्भपात के मामले में: गर्भपात होने पर लाभार्थी महिला की बची हुई किस्तें, आगे कभी गर्भधारण की स्थिति में प्राप्त की जा सकती हैं। बाद के गर्भधारण के दौरान वे किस्तें दोबारा नहीं मिलेंगी, जो पहले वाले गर्भधारण के दौरान उसे मिल चुकी हैं। उदाहरण के लिए किसी महिला को पहले गर्भधारण के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की पहली किस्त मिल चुकी है। इसके बाद अगर उसका गर्भपात होता है तो उसे अगले गर्भधारण व संतान उत्पत्ति के दौरान सिर्फ दूसरी व तीसरी किस्त मिल सकेगी।

मृत शिशु जन्म के मामले में: मृत शिशु पैदा होने की स्थिति में भी यही नियम लागू होंगे। यानी कि जो किस्तें पहले मिल चुकी हैं, वे दोबारा नहीं मिलेंगी और जो किस्ते पहले नहीं प्राप्त की गई हैं, उनके लिए अगले गर्भधारण की स्थिति में क्लेम किया जा सकता है।

शिशु मृत्यु के मामले में: शिशु की मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ पाने के नियम इसी प्रकार रहेंगे। अगर, लाभार्थी महिला ने योजना के तहत मिलने वाली सभी किस्तें प्राप्त कर ली हैं तो अगले गर्भधारण व संतान को जन्म देने की स्थिति में वह किसी प्रकार के लाभ का दावा नहीं कर सकती। अगर कोई किस्त बची हुई है तो उसे वह बाद में क्लेम कर सकती है।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

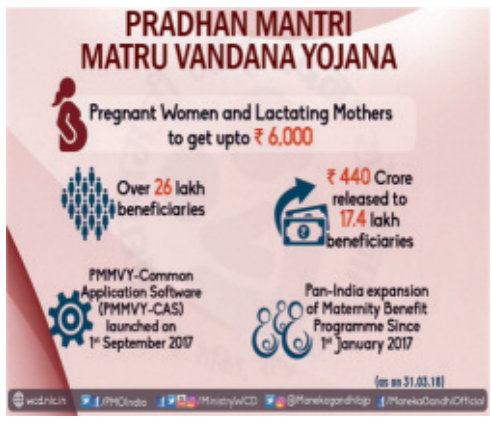

योजना का लाभ पाने के लिए आपको आसपास मौजूद आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में संपर्क करना होगा। आंगन बाड़ी कार्यकर्ता, आशा या एनएएम स्वयं ही आपसे सारी जानकारी लेकर फॉर्म भर देगी और उसे आगे की प्रक्रिया के लिए भिजवा देगी।

कहां करें आवेदन

आंगनवाड़ी केंद्र: जिन राज्यों में कुपोषण मिटाने की योजना आईसीडीएस (समेकित बाल विकास सेवाएं) महिला एवं बाल विकास विभाग समाज कल्याण विभाग के माध्यम से लागू की जा रही है, वहां आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित होगी।

स्वास्थ्य सुविधा केंद्र: जिन राज्यों में कुपोषण मिटाने की योजना आईसीडीएस (समेकित बाल विकास सेवाएं) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से लागू की जा रही है, वहां प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

आवेदन के लिए अर्हता व जरुरी दस्तावेज

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 6000 रुपये की सहायता योजना गर्भवती महिलाओं के लिए डाउनलोड करें आवेदन पत्र

आवेदन फार्म भरने के लिए महिला की आयु 19 साल से अधिक होनी चाहिए। मदद की तीनों किस्तों के क्लेम के लिए अलग-अलग फार्म भरे जाएंगे।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए जाने आवश्यक हैं-

आधार कार्ड की फोटोकॉपी: लाभार्थी महिला और उसके पति के आधार कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न की जानी चाहिए। महिला लाभार्थी की पहचान प्रमाण में यह सबसे पुख्ता दस्तावेज है। आधार न होने पर उसके लिए आवेदन के बाद मिली आधार नामांकन संख्या दर्ज करनी होगी और पहचान प्रमाण का कोई अन्य वैध दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा।

मान्य दस्तावेजों की सूची:

बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता की पासबुक: लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट या डाकघर अकाउंट की फोटोयुक्त पासबुक की फोटोकॉपी। इसी खाते में सरकार की ओर से भेजी गई मदद की राशि भेजी जाएगी। बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस अकाउंट ऐ आधार से लिंक भी कराया जाना चाहिए।

आधार न होने पर पहचान संबंधी अन्य विकल्प-लाभार्थी महिला व उसके पति, जिसका भी आधार नंबर उपलब्ध नहीं हो सका है, उसे अपनी पहचान प्रमाण के लिए रूप में

निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की फोटोकॉपी संलग्न कर सकते हैं-

मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, किसान फोटो पासबुक, पीएचसी या सरकारी अस्पताल से जारी स्वास्थ्य कार्ड, सरकारी विभाग कंपनी संस्थान से जारी कर्मचारी पहचान पत्र, कोई अन्य सरकारी फोटो व अन्य विवरण युक्त दस्तावेज, गजटेड ऑफिसर के लेटरहेड पर जारी फोटोयुक्त पहचान प्रमाण

क्लेम के 30 दिन के अंदर खाते में पहुंचेगा पैसा आवेदन के तहत ठीक प्रकार से भरे हुए फॉर्म के साथ क्लेम किए जाने के बाद अधिकतम 30 दिन के भीतर उसे मदद राशि मिल जानी चाहिए। सभी किस्तें सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएंगी।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए फॉर्म

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अलग-अलग तरह के कामों के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। इनमें लाभार्थी महिला की ओर से भरे जाने वाले फॉर्मों की सूचीः

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में रजिस्ट्रेशन व क्लेम से संबंधित फॉर्म

फार्म 1 - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली बार पंजीकरण और पहली किस्त का क्लेम करने के लिए आवेदन फॉर्म

फार्म 1 - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दूसरी किस्त पाने की खातिर क्लेम करने के लिए आवेदन पत्र

फार्म 1 - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत तीसरी किस्त पाने की खातिर क्लेम करने के लिए आवेदन पत्र

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए दस्तावेज लिंक कराने से संबंधित फॉर्म

फार्म 2 - लाभार्थी महिला के बैंक खाते को आधार से स्पदा करवाने (जोड़ने) के लिए आवेदन फॉर्म

फार्म 2 - लाभार्थी महिला के डाकघर खाते को आधार से स्पदा करवाने (जोड़ने) के लिए आवेदन फॉर्म

फार्म 2 - लाभार्थी महिला का आधार उपलब्ध न होने पर आधार नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म या फिर आधार में किसी तथ्य के बदलाव के लिए संशोधन फार्म

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

मिशन रीव... सफलता भरा एक वर्ष...

मिशन रीव की विभिन्न गतिविधियों और कुछ यादगार लम्हों को 'द रीव टाइम्स ' के इस अंक में आप से साझा कर रहे हैं।

विदेशों में भी रीव की मांग से इसकी सार्थकता पर लगी मुहर

आईआईआरडी का प्रतिनिधि मंडल अराईज़ इंडिया के साथ जिनेवा में यूएन की बैठक में मिशन रीव पर चर्चा के साथ हाल ही में भारत लौट आया है। प्रतिनिधि मंडल में चेयरमैन प्रो आर के गुप्ता, प्रबंध निदेशक डॉ. एल सी शर्मा, निदेशक सुषमा शर्मा एवं निदेशक मंडल के सदस्य ब्रिगेडियर वी के खन्ना शामिल थे। अपने प्रस्तुतिकरण में ब्रिगेडियर खन्ना और डॉ. एल सी शर्मा ने मिशन रीव की आज के संदर्भ में प्रासंगिकता को बेहतर तरीके से सामने रखा जिसे 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने सुना और सराहा भी। डॉ. एल सी शर्मा ने बताया कि मिशन रीव जन सेवा और सामाजिक विकास के ताने-बाने में सर्वथा उपयुक्त है जिसे हिमाचल प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों और अब विदेशों में भी सराहना मिल रही है।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी से भी मिली सराहना

आईआईआरडी वर्ष 2018 से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का साझेदार है। इसके तहत हिमाचल और उत्तर प्रदेश में कौशल विकास प्रशिक्षण को लेकर विभिन्न केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनवरी 2019 में प्रशिक्षण पूरा कर चुके अभियर्थियों को पत्र देने के मौके पर आईआईआरडी द्वारा यूपी में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यअतिथि शिरकत की। उन्होंने कौशल विकास को लेकर आईआईआरडी के प्रयासों की सराहना की और कौशल प्राप्त कर चुके अभियार्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए।

महिला सशक्तिकरण में संस्था की उड़ान...

वर्ष 2019 में आईआईआरडी को राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि से नवाज़ा गया संस्था का चयन कार्यस्थल पर महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्कृष्ठ माहौल के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क ईंडिया द्वारा चयन किया गया। समय–समय पर महिलाओं के कल्याण लिए संस्था द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास नियमित रुप से किए जाते हैं जिससे महिला सशक्तिकरण में संस्था के प्रयासों को पुरस्कृत होने का अवसर प्राप्त हुआ। राजधानी दिल्ली में संस्था की ओर से प्रबंध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा ने प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने संस्था की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि आईआईआरडी में महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले समान अनुपात है और कार्यालय में निचले स्तर से उच्च स्तर तक महिलाओं ने अपनी योग्यता को साबित किया है।

भारतीय जीवन बीमा से साझेदारी

वर्ष 2019 की शुरूआत के साथ ही मिशन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल ही। जीवन सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ साझेदारी कर राष्ट्रीय स्तर पर कॉरपोरेट सदस्यता प्राप्त की। इस साझेदारी के बाद मिशन रीव ने हिमाचल के गांवों में उन लोगों का बीमा से जोड़ा जिन्हें न तो जीवन बीमा के महत्व कराने के बारे में कोई जानकारी थी और न ही खुद को बीमित करने का कोई माध्यम। इसके लिए मिशन रीव की ओर से चंबा, ऊना, सोलन, शिमला में इसके लिए विशेष ड्राइव चलाई गई आरै एलआईसी के अधिकारियों को साथ लेकर लोगों को जीवन सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। इसके बाद उन्हें एलआईसी पॉलीसी लेने में भी सहयोग किया जा रहा है।

एसीएस स्वास्थ्य द्वारा 5 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन–

16 जुलाई का दिन आईआईआरडी मिशन रीव के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी काफी अहम रहा। इस दिन तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव और वर्तमान मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने आईआईआरडी मुख्यालय शिमला से पांच जनऔषधि केंद्रों का उद्घाटन किया और केंद्र संचालकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान शिमला, मंडी के छतरी, बंगरोटू, कांगड़ा के नूरपुर व पालमपुर और हमीरपुर के जाहू में जनऔषधि केंद्रों का उद्घाटन हुआ। इसके बाद कुल्लू, चंबा समेत अन्य जिलों में जनऔषधि केंद्र खोलने का सिलसिला लगातार जारी है।

द रीव टाइम्स का पहला अंक प्रकाशित

15 जुलाई 2018 को मिशन रीव के तहत गांव के लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स का प्रकाशन शुरू किया गया। आज प्रदेश की लगभग हर पंचायत तक द रीव टाइम्स पहुंच रहा है।

मृदा परीक्षण सुविधा का शुभारम्भ

मिशन रीव के तहत गांव के किसानों की खेती को और बेहतर बनाने के लिए जैविक खाद के बाद मृदा परीक्षण की सुविधा को भी सितं बर 2018 में मिशन रीव की सेवाओं में शामिल किया गया। हाल ही में उपरी शिमला में विभिन्न स्थानों पर मृदा परीक्षण शिविरों का सफल आयोजन किया गया। इसमें 100 से अधिक किसानों ने मृदा जांच के लिए अपने खेतों की मिट्टी दी और इन किसानों को जांच के बाद रिपोर्ट भी दी गई।

मिशन रीव संस्करण का जोरदार आगाज...

मिशन रीव के पहले संस्करण के सफल कार्यान्वयन के बाद लोगों को और अधिक बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए मिशन रीव संस्करण दो के आगाज पर चंबा, सोलन, ऊना और बिलासपुर में विषेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मिशन रीव संस्करण–दो सबसे बड़ी खासियत इसकी नवसंरचना है। मिशन रीव –दो को तकनीकी से जोड़ कर इसे और अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया और साथ ही लोगों को उनकी आवश्यकता के मुताबिक सेवांए देने के लिए दस अलग–अलग डिविजन बनाए गए।

शिक्षा मंत्री ने जिंदगी जियें– नशे को नहीं अभियान के विजेताओं को नवाजा

2 अक्तूबर 2018 को गांधी जयंती के अवसर पर आईआईआरडी के जिदंगी जियें– नशे को नहीं अभियान के समापन अवसर पर आईआईआरडी कार्यालय में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश शिक्ष मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अभियान के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर शिमला नगर निगम की महापौर कुसम सदरेट भी बतौर विशेष अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित रहीं।

उड़ीसा में अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण

एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान (आईआईआरडी) प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा है। यही वजह है कि अंतराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भी आईआईआरडी के साथ मिलकर काम कर रही है। आईआईआरडी हिमाचल की पहली ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) प्रोजेक्ट को पूरा करने में अहम योगदान दे रही है। इसका एक उदाहरण उड़ीसा में आईआईआरडी और गेल की साझेदारी से बन रहा इंडोर स्टेडियम है। सीएसआर के तहत इस प्रोजेक्ट को आईआईआरडी गेल इंडिया के साथ मिलकर पूरा करेगा। उड़ीसा के बारंगिल में बनने वाले इस स्टेडियम का इसका शिलान्यास साल के शुरूआती माह में ही किया गया। यह शिलान्यास तत्कालीन केंद्रीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है। इस मौके पर गेल इंडिया और आईआईआरडी के अधिकारी भी मौजूद रहे।

आसाम में भी आईआईआरडी के स्मार्ट क्लास रुम

आईआईआरडी के स्मार्ट क्लास रुम पर भारत के विभिन्न राज्यों में किए गए प्रयासों को सराहना मिल रही है। इसी प्रयास में अब आसाम में भी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए संस्था स्मार्ट क्लास रुम शुरु करने जा रही है। आरंभिक तौर पर आसाम के 30 विद्यालय इससे लाभान्वित होंगे। इन स्कूलों में 60 स्मार्टक्लास रुम स्थापित किये जा रहे हैं। इससे सरकारी विद्यालयों के बच्चों को गुणवत्ता तथा तकनीकि शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। इन स्मार्ट क्लास रुम में अत्याधुनिक तकनीक से लर्निंग करवाई जाएगी।

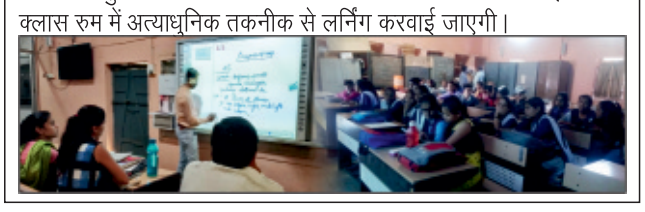

उत्कृष्ठ एनजीओ ऑफ सीएसआर टाइम्स पुरस्कार

आईआईआरडी को उत्कृष्ठ एनजीओ ऑफ सीएसआर टाइम्स का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार झारखंड में आईआईआरडी की ओर से जनजातीय महिलाओं के उत्थान के लिए चलाए गए प्रोजेक्ट रूपांतरण के बेतरीन कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया।

कनार्टक में ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास

अक्तूबर 2018 में आईआईआरडी की ओर एक और उपलब्धि हासिल की गई। अक्तूबर 2018 को कनार्टक के धारवाड़ में बहुद्देशिय इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया गया और अब कार्य प्रगति पर है।

आईआईआरडी में खुला रीव क्लीनिक

आईआईआरडी के मिशन रीव के तहत शिमला मुख्यालय में रीव क्लीनिक की शुभारंभ भी अक्तूबर 2018 में किया गया। यह क्लीनिक अत्याधुनिक टेस्ट सुविधाओं से लैस है और यहां पर ईसीजी कराने की सुविधा भी मरीजों को मिल रही है।

आईआईआरडी को एनएसडीसी से मिला पार्टनरशिप सर्टीफिकेट

नवंबर 2018 – हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की ओर से आईआईआरडी को हिमाचल में पांच केंद्र चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें 300 अभ्यर्थियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।

चंबा पहला कैशलैस जिला

मिशन रीव की ओर से चंबा में एक बेहतरीन पहल की जा रही है। बीते सितंबर मे मिशन रीव के तहत सभी प्रतिनिधियों को पीओएस मशीनें दी गई थी। इन मशीनों को देने का मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों को सेवा प्राप्ती के लिए कैश रखने की परेशानी से मुक्त करना है। चंबा की तर्ज पर मिशन रीव के तहत अन्य जिलों में भी जल्द ही पीओएस मशीनों से ही सभी भुगतान किया जाएगा और सभी मिशन प्रतिनिधियों को पीओएस मशीने दी जाएंगी। चंबा के जिला समन्वयक राकेश शर्मा का कहना है कि मिशन रीव चंबा को कैशलैस करने की ओर से तेजी से अग्रसर है। अधिकतर प्रतिनिधियों को पीओएस मशीनें दी जा चुकी है और जहां किन्हीं कारणों से मशीनें नहीं पहुंच पाई वहां भी जल्द ही पीओएस से भुगतगान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

विकास खण्ड मशोबरा की 48 पंचायतों में मिशन रीव की धमक...

मिशन रीव ने अपने दूसरे संस्करण के तहत सेवाओं और घर - गांव में ही रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ज़िला शिमला में विभिन्न पंचायतों का दौरा किया गया। इसके लिए सर्वप्रथम शिमला के विकास खण्ड मशोबरा को चयनित कर खण्ड की 48 पंचायतों में मिशन रीव के सेवाकर्मी वहां के पंचायत प्रतिनिधियों एवं सचिवों से मिले। इसके अलावा गांव में जाकर लोगों से भी रीव पर चर्चा की गई। विकास खण्ड में समस्त 48 पंचायतों में मिशन रीव के रीव ऐसोसियेटस की भर्ती की जानी है जिनकी संख्या 3 होगी। इन रीव एसोसियेटस के लिए एनएसडीसी प्रमाणित सर्टिफिकेट कोर्स होगा। आईआईआरडी एनएसडीसी के साथ अधिकारिक एसोसियेशन में है तथा हिमाचल में 10 हज़ार युवाओं को इस सर्टिफिकेट कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विरेंद्र कंवर द्वारा मिशन रीव की विभिन्न सेवाओं का आगाज

मिशन रीव की सफलता के इतिहास में फरवरी 2018 को एक नया अध्याय उस समय जुड़ गया जब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विरेंद्र कंवर ने आईआईआरडी शिमला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मिशन रीव की विभिन्न सेवाओं का लोकापर्ण किया। उन्होंने उस दौरान कहा कि मिशन रीव गांव के विकास का बहुत बड़ा मिशन साबित होगा।

ब्लॉक स्तर पर खुले कार्यालय

मई 2018 – प्रदेश के गांव गांव तक मिशन रीव की सेवाओं को सरल और सुलभ तरीके से पहुंचाने के लिए विभिन्न ब्लॉक कार्यालयों की स्थापना की गई जहां से मिशन रीव की सेवाओं से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

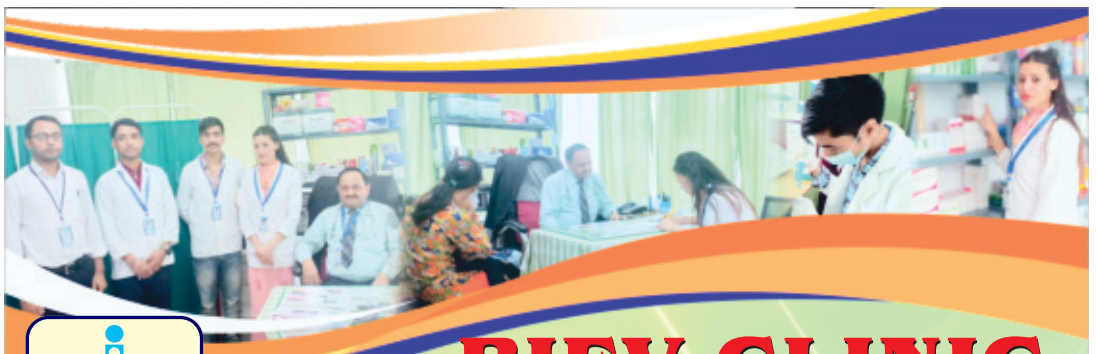

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर
Institute for Integrated Rural Development

RIEV-CLINIC

A constituent unit of
INSTITUTE FOR INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT
(Approved from Health Department, Govt of H.P.)

Diagnostics •Consultancy •Path Lab •Wide Range of Medicines

A Unique Integrated Health Care Center

Under the Patronage of *Dr. K.R. Shandil*, Former HOD (Path & Medicine) IGMC-Shimla

Comprehensive Health Services Under Single Roof

CONSULTANCY
Dr. K.R. Shandil
- HOD (Health) Mission-RIEV
- Former HOD (Path & Medicine) IGMC Shimla

- Pathology expertise
- Medication consultancy
- Diet plan
- Diagnostic expertise
- Periodic health monitoring

PATH LAB
- Mr. Rahul
- Mr. Vijay Thakur
- Phlabotomist & Experienced Technician (More than 4 year experience)

- Biochemistry
- Urine analysis
- Haemetalogy (All type of blood test)
- Discounted full package-1450
- Package without thyroid-1000
- Home collection | Report with in 3hrs

NURSING HOME CARE
- Ms. Neelam
- Experienced GNM (More than 5 year experience)

- Child care
- Assistance in injectables
- Assistance in medicine counselling
- ECG

MEDICATION AND HEALTH SUPPLEMENTS
- Ms. Kumari Neelam
- Registered Pharmacist (More than 5 year experience)

- Wide range medicines
- Surgicals
- Diverse range of Janaushadhi
- Herbal products
- Nutrient supplements

By Pass Road, Shanan, Sanjauli, Shimla H.P. 171006, India
Contact :- 0177-2843528, Email : info@iirdshimla.org, Website : iirdshimla.org

Thakur Graphics
Printing Professional

THAKUR GRAPHICS

All Kind of Offset Printing & Screen Printing

- Visiting Card, Bill Book, Brochure, Leaflets
- Posters, Stickers, School Magzine, Souvenir
- Designing, Typing, Scanning, Colour Printouts
- Digital Flex, Glow Sign Board & ACP Board

Krishna Bhawan Nr. Auckland School, Lakkar Bazar
Shimla - 171001 (H.P.)
94180 48492
0177 2808492
Email : thakurgraphics@gmail.com

WE ARE HIRING

BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVES

MBA or EQUIVALENT IN SHIMLA

EXPLORE THE UNIVERSE OF BUSINESS OPPORTUNITIES

Recruitment	Business Development Executive (BDE)
Location	Shimla City
Number	100
Eligibility	MBA or equivalent
Training	As per NSDC pattern (200 hrs training at IIRD, Shanan)
Mandatory	Laptop
Training Certification Fee	Rs. 10000/-
Salary	Rs. 15000/- for first 3 months during probation
Present Position	Shimla city for 3 months including training period
Post 3 months	All to be deployed at each block headquarter
Salary post probation	Rs. 20,000/-* T&C Apply*

Visit to know more & Apply at : www.recruitment.missionriev.in

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर

Last Date for Submission of Appliction is 20-08-2019

MISSION RIEV
Ruralising India- Empowering Villages

For Detail Contact : 0177 2844073, 78760 52696, 82196 94079

IIRD Complex, Bypass Road, Shanan, Sanjauli, Shimla, H.P.-171006 Email : info@iirdshimla.org

With Best Wishes

HIMSTAR VIEW

A sense of warmth and relaxation... Feel at home

HIM STAR VIEW ROAD MAP

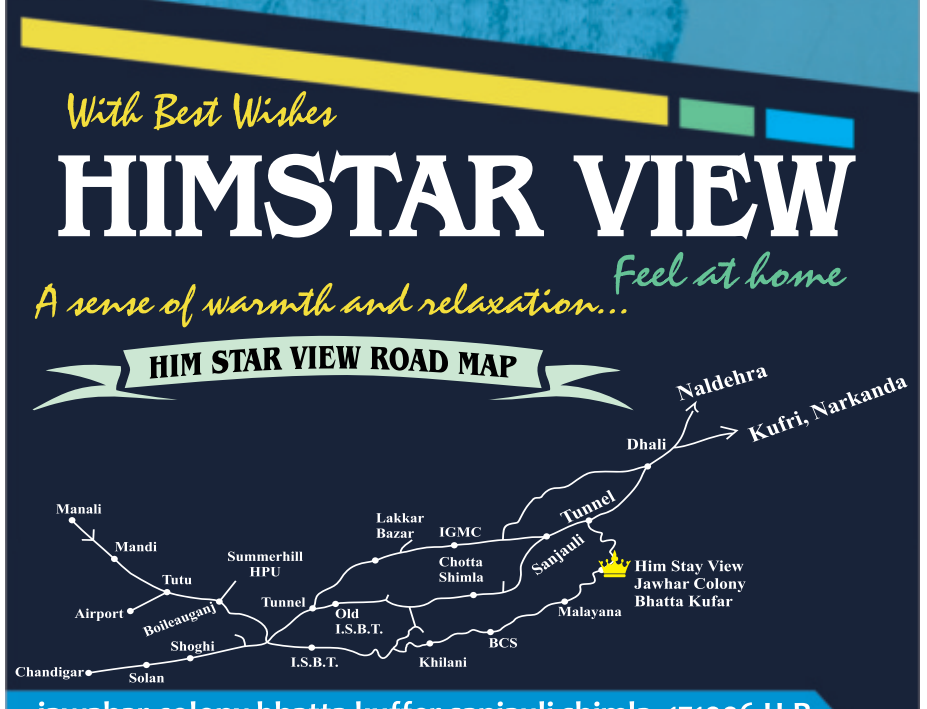

jawahar colony bhatta kuffer sanjauli shimla, 171006 H.P.
Contact : 9318599082, 9218599082